छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 07 ■ अम्बिकापुर, बुधवार 24 दिसम्बर 2025 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

एनएच में गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण कार्य, उप अभियंता प्रभाव से निलंबित

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। लोक निर्माण विभाग ने गुणवत्ताहीन सड़क पैंच रिपेयरिंग कार्य पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उप अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 के अंबिकापुर शहरी भाग में कराए गए गुणवत्ताविहीन बी.टी. पैच रिपेयर कार्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता कार्यालय में पदस्थ उप अभियंता नवीन सिन्हा को विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 के अंबिकापुर शहरी भाग में कराए गए बी.टी. पैच रिपेयर के गुणवत्ताहीन कार्य पर संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिवेदन एवं तस्वीरें राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर के मुख्य अभियंता को प्रेषित की गई थी। मुख्य अभियंता द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य के लिए जिम्मेदार उप अभियंता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित किया गया था। लोक निर्माण विभाग ने गुणवत्ताहीन कार्य पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उप अभियंता नवीन सिन्हा के तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश आज जारी कर दिया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कांग्रेस पार्टी करेगी निगरानी, नागरिकों ने कहा-खुलेआम हो रहा स्तरहीन काम

शहर के अंदर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के आगामी सभी मरम्मत कार्य की निगरानी कांग्रेस पार्टी करेगी। इन मार्गों में खराब पैंच रिपेयरिंग की शिकायत के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने इन सड़कों का अवलोकन करने और इस कार्य को कराने वाले ठेकेदार से चर्चा के बाद यह जानकारी दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने घटिया पैच रिपेयरिंग की जानकारी के बाद न केवल इन सड़कों का अवलोकन किया, साथ ही यहां के रहवासियों से भी चर्चा की। सभी ने यह शिकायत की कि सड़कों का पैंच रिपेयरिंग स्तरहीन है। जिन गड्ढों पर पैंच चढ़ाया गया है वो उखड़ रहे हैं। बगैर सफाई के पैच रिपेयरिंग का काम हो रहा है। सड़कों के मरम्मत में खुलेआम हो रहे इस घटिया काम और भ्रष्टाचार से लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था। लंबे अर्से से शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़कों का रख-रखाव इस विभाग ने नहीं किया है। इन सड़कों के रख-रखाव का इस वर्ष लगभग 8 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ है, और अब ठेकेदार के द्वारा निम्न स्तर का रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा है।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने ठेकेदार को फटकारा

सड़कों के अवलोकन दौरान ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मोबाइल फोन पर इस कार्य को कर रहे ठेकेदार को फटकार लगाई और उसे निर्देशित किया कि जब भी वह कार्य आरंभ करे, इसकी पूर्व सूचना दे। कांग्रेस का दल उसके कार्य की निगरानी करेगा। पूर्व महापौर एवं लुंड्रा विधायक तथा भाजपा जिलाध्यक्ष के निवास से गुजरने वाली सड़क के घटिया निर्माण पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, दिया तले अंधेरा है। इस सड़क का निर्माण नगर निगम के द्वारा कराया गया है, बनते ही यह सड़क उखड़ गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि निगम की सत्ता में आने के बाद ट्रिपल इंजन के विकास के नाम पर चौड़ी-चौड़ी फोरलेन सड़कों के चित्र दिखलाकर मायाजाल फैलाने वाले लोगों के घर के सामने से गुजरने वाली सड़क बनते ही उखड़ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रिपल इंजन के नाम से विकास का दावा खोखला दावा भर ही है।

मां समलाया के नाम पर मंडल गठन करने वाले कर रहे मौजमस्ती

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि मां महामाया और मां समलाया इस क्षेत्र की आराध्य देवी हैं। भाजपा ने उनके नाम पर अपने मंडलों का गठन कर लिया है और मां समलाया के नाम पर मंडल गठित कर मां समलाया मंडल वाले मौजमस्ती कर रहे हैं। ये हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है।

गौ वंशों को बूचड़खाना ले जाते पिकअप सहित चालक गिरफ्तार

13 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक बांधकर ले जा रहा था, एक की हुई मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कोतवाली पुलिस ने गौ वंशों की तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया, और 13 नग मवेशी एवं पिकअप वाहन को जप्त किया है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बांकी डैम के पास पिकअप वाहन को रोका, जिसमें मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर भरा गया था।

जानकारी के मुताबिक अंकित तिवारी पिता देवी प्रसाद तिवारी निवासी घुटरापारा अंबिकापुर ने 23 दिसम्बर को अलसुबह करीब 5 बजे पुलिस को अवगत कराया था कि बाकी डैम के पास एक पिकअप में गौ वंशों को क्रूरता पूर्वक भरकर झारखंड बूचड़खाना ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने थाना कोतवाली में छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 व पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान आवेदक एवं उसके साथी प्रतीक गुप्ता, विशाल केसरी, स्वास्तिक एवं अन्य साथियों के साथ पुलिस टीम बाकी डैम के पास पहुंची, और पिकअप वाहन क्रमांक जेएच 17 जेड 2975 को रोककर तिरपाल खोलवाया। अंदर का नजारा देखकर पुलिस दंग रह गई। 13 गौ वंशों का चारों पैर एवं सिर को रस्सी से क्रूरता पूर्वक बांधकर रखा गया था, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई थी। आरोपी पिकअप चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर वह बताया कि सभी गौ वंशों को भरकर काटने के लिए बूचड़खाना झारखंड ले जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी वाहन चालक हैय्युल खान उर्फ हैलू खान पिता खलील खान 24 वर्ष निवासी साईं टांगर टोली ईदगाह मोहल्ला लोदाम जिला जशपुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। शेष 12 मवेशियों को गौ सेवा सदन में सुरक्षार्थ रखवाया गया। एक मृत मवेशी के कफन-दफन हेतु नगर पालिक निगम अंबिकापुर के सुपुर्द किया गया।

ज्वेलरी दुकान के संचालकों ने साइबर पुलिस टीम को भेंट किया स्मृति चिन्ह

मामला जगदम्बा आभूषण भंडार में चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को पकड़ने से जुड़ा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सदर रोड स्थित जगदम्बा आभूषण भंडार में चोरी का प्रयास करने वाले बुर्काधारी चोर की गिरफ्तारी पर पुलिस विभाग के साइबर सेल अंबिकापुर की टीम का सर्राफा व्यवसायियों ने आभार जताया है। सर्राफा व्यापारियों ने इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद ज्ञापित किया, उन्होंने इस कार्रवाई का श्रेय साइबर थाना पुलिस को दिया, और साइबर पुलिस की टीम को स्मृति चिह्न भेंट करने की अनुशंसा की।

बता दें कि 13 दिसम्बर को सदर रोड स्थित जगदम्बा आभूषण भंडार में चोर ने रात्रि करीब 11 बजे दुकान के सीसीटीव्ही कैमरा एवं बिजली कनेक्शन का तार काटकर दुकान से सोना-चांदी चोरी करने का प्रयास किया था। मामले में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके पुलिस ने विवेचना में लिया। विवेचना दौरान थाना अंबिकापुर एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा शहर में लगे पुलिस विभाग एवं निजी करीब 100 से अधिक सीसीटीव्ही के वीडियो फुटेज का अवलोकन किया और पूछताछ करते हुए आरोपी के ठिकाने का पता लगाया। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा था। 23 दिसम्बर को सदर रोड स्थित जगदम्बा आभूषण भंडार के संचालक कृष्ण प्रसाद सोनी, राजा सोनी के साथ अन्य आभूषण व्यापारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्मृति चिह्न भेंट करने उनके कार्यालय पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने इस सफलता का श्रेय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा अमोलक सिंह ढिल्लो एवं नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के मार्गदर्शन में कार्य कर रही साइबर सेल अंबिकापुर के पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को देकर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने की अनुशंसा की। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुशंसा पर सर्राफा व्यापारियों ने पूरी टीम को उनके मेहनत एवं लगन से कार्य करने और बेहद कम समय में आरोपी का पता लगाकर न्यायिक रिमांड पर भेजने में योगदान देने के लिए पुलिस टीम के सदस्य सहायक उप निरीक्षक अजीत कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, जयदीप सिंह, विकास सिन्हा, आरक्षक मनीष सिंह, जितेश साहू, रमेश राजवाड़े, अमित विश्वकर्मा, नितिन सिन्हा का सहृदय आभार व्यक्त करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया।

पुलिस वाहनों की आवाजाही से घबराकर भागा था चोर

चोर ने पूछताछ में बताया था कि वह पूरी तैयारी से चोरी करने की नियत से जगदम्बा आभूषण भंडार में आया था। वेल्डिंग कटर की सहायता से दुकान का वेंटिलेशन काटकर चोरी की घटना करने वाला था, कुछ औजार गलती से घर में ही छूट जाने के कारण समय अधिक लगा और पुलिस गाड़ियों की आवाजाही से घबराकर भाग गया। गिरफ्तार आरोपी की थाने में विधिवत तलाशी ली गई थी, और घटना में प्रयुक्त वेल्डिंग मशीन, प्लायर वायर, कटर, वेल्डिंग रॉड, टार्च, वॉयर एक्सटेंशन इत्यादि बरामद किया था। चोर की मंशा आभूषण भंडार से भारी मात्रा में सोना-चांदी एवं नकदी रकम चोरी करने की थी। साइबर सेल के अधिकारी-कर्मचारियों ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके चोर को तलाशने में सफल हुए और उसे समय पर हिरासत में ले लिया, जिससे पुन: अन्य ज्वेलरी शॉप में चोरी की बड़ी घटना नहीं हुई।

सड़क हादसे में घायल ग्रामीण की मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सड़क दुर्घटना में घायल सूरजपुर जिला के भटगांव थाना अंतर्गत ग्राम केवटाली निवासी अमिर साय सोनपाकर 43 वर्ष की मौत हो गई। मृतक 22 दिसम्बर को सुबह करीब 10 बजे ग्राम सत्यनगर से ट्रेक्टर किराए में लेकर अपने पुत्र पुरषोत्तम सोनपाकर के साथ गोबर खाद लेने के लिए मोटरसायकल से गया था। पुरषोत्तम दोपहर करीब 2.30 बजे ट्रेक्टर में खाद लेकर वापस आ गया, लेकिन उसके पिता नहीं पहुंचे थे। कई बार मोबाइल में फोन करने के बाद अज्ञात व्यक्ति फोन उठाया और बताया कि भटगांव थाना क्षेत्र के फुटाबांध जंगल के पास फोनधारक का एक्सीडेंट हो गया है, और वे बेहोशी की हालत में हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुत्र सहित अन्य मौके पर पहुंचे तो उसके पिता के सिर, कान में चोट लगा था, जिससे खून निकल रहा था। घटनास्थल पर एक अज्ञात मोटरसायकल का वाइजर टूटा हुआ था। घायल अवस्था में वे उन्हें भैयाथान स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, यहां से प्राथमिक इलाज के बाद होली क्रॉस अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर दी जानकारी

22 जनवरी तक लिए जाएंगे दावा-आपत्ति, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन मंगलवार 23 दिसंबर को किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिले में संपादित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप (ड्राॅफ्ट) मतदाता सूची आज 23 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित की जा रही है। दावा एवं आपत्ति अवधि 23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित है, जिसमें पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा अपात्र नाम कटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन अनुसार जिले में कुल मतदाता 5 लाख 98 हजार 492 है, जिनमें से 02 लाख 99 हजार 614 पुरुष मतदाता एवं 02 लाख 98 हजार 862 महिला मतदाता तथा 16 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 01 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 साल पूर्ण कर लिया गया है तथा जिनका नाम वर्तमान में किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं करा पाया है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु फार्म 6 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले वोटर द्वारा इलेक्टोरल रोल में शामिल करने के लिए फार्म 6।, मौजूदा इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने/हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए वोटर एप्लीकेशन फॉर्म 7, कोई मतदाता अपने नाम एवं अन्य किसी प्रकार का संशोधन या पते में परिवर्तन करना चाहते हैं वे फार्म-8 के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। एप्लीकेशन फॉर्म अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं या ईसीआई नेट,मोबाइल एप के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण करने के पश्चात जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 876 है। पूर्व में मतदान केंद्र की संख्या 782 थी, जिसमें 94 की वृद्धि हुई है। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक, सर्व एसडीएम सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सात दशक से काबिज भूमि से बेदखल परिवार राष्ट्रपति से लगाया इच्छामृत्यु की गुहार

आंगनबाड़ी भवन के निर्माण की रखी नींव, परिवार में 4 सदस्य हैं दिव्यांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। आंगनबाड़ी भवन निर्माण को लेकर एक परिवार को भूमि से बेदखल करने का मामला सामने आया है। मामला सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बटईकेला स्थित खसरा नंबर 1784 का है, जहां शासकीय भूमि पर आंगनबाड़ी निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पर केवला बाई और उनके परिवार के सदस्यों ने आपत्ति जताई है। केवला बाई के परिवार में कुल 12 सदस्य हैं, जिनमें चार दिव्यांग हैं। इनका कहना है कि यदि उनकी खेती की जमीन छिन गई तो उनके सामने भोजन और आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसी मानसिक दबाव और प्रशासनिक कार्रवाई से आहत होकर उक्त परिवार ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने इसे लेकर सीतापुर विधायक से भी नाराजगी जताई है।

केवला बाई का आरोप है कि वे पिछले लगभग 70 वर्षों से इसी भूमि पर खेती-किसानी करके अपना जीवनयापन करते आ रहे हैं। भले ही राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि शासकीय दर्ज हो, लेकिन इसे कृषि योग्य बनाने में उनके पूर्वजों की वर्षों की मेहनत लगी है, आज भी यह जमीन उनके परिवार की एकमात्र आजीविका का साधन है। आरोप है कि ग्राम पंचायत के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना, चर्चा या ग्राम सभा की अनुमति के जबरन आंगनबाड़ी निर्माण की नींव डाल दी गई। पूरे मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और निर्माण से जुड़े ठेकेदार पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि आंगनबाड़ी निर्माण का स्थान जान-बूझकर इसी भूमि पर चुना गया, जबकि गांव में अन्य वैकल्पिक शासकीय भूमि उपलब्ध है। आरोप यह भी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने निज लाभ के लिए भवन को अपने निवास के समीप बनवाना चाहती है। शिकायत में कहा गया है कि इसी खसरा नंबर की शासकीय भूमि पर ग्राम पंचायत के एक जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा पहले से ही अतिक्रमण करके पक्का मकान बनाया गया है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। इधर केवला बाई के परिवार को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जिसे पीड़ित परिवार ने पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण बताया है। शिकायत पत्र की प्रति राज्यपाल, प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है, ताकि संवैधानिक संरक्षण और त्वरित हस्तक्षेप हो सके। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, अवैध निर्माण पर रोक लगे और वर्षों से काबिज परिवार को न्याय मिले। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा तेजी से गरमा रहा है। ग्रामीणों की नजरें अब शासन-प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

कोयला कर्मियों के भविष्य निधि पर बढ़ा ब्याज, 7.7 प्रतिशत पर बनी सहमति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कोयला खदानों में कार्यरत लाखों कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम फैसला सामने आया है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन की 185 वीं ट्रस्टी बोर्ड बैठक हाल ही में सम्पन्न हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि पर 7.7 प्रतिशत ब्याज दर देने पर सहमति बनी। यह प्रस्ताव अब औपचारिक स्वीकृति हेतु कोयला मंत्रालय को भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7.6 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई थी। इस लिहाज से नई दर में 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिसे कोयला कर्मियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। ट्रस्टी बोर्ड की बैठक के दौरान प्रबंधन पक्ष ने 2024-25 की तरह ही 7.6 प्रतिशत ब्याज दर को यथावत रखने का सुझाव दिया। वहीं मजदूर प्रतिनिधियों की ओर से अधिक ब्याज दर की मांग जोर-शोर से उठाई गई। एटक नेता रमेंद्र कुमार ने कर्मियों के हित को ध्यान में रखते हुए 7.8 प्रतिशत ब्याज दर देने की पुरजोर मांग रखी। इस पर विस्तृत चर्चा के बाद अंततः 7.7 प्रतिशत ब्याज दर पर सभी पक्षों की सहमति बनी। बैठक में केवल ब्याज दर ही नहीं, बल्कि कई अन्य अहम विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। इनमें प्रमुख रूप से सी-डेक से जुड़े तकनीकी मुद्दे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिवाइज्ड पीपीओ को स्वीकार न करने से उत्पन्न समस्याएं, पेंशनधारियों और कर्मियों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों विषयों पर समाधान की दिशा में चर्चा की गई। बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सीएमपीएफओ के सभी रीजनल कार्यालयों के नवीनीकरण पर सहमति बनी। इससे न केवल कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा, बल्कि कर्मियों और पेंशनधारियों को बेहतर सेवाएं भी मिल सकेंगी।

स्वीकृत गतिविधियों का क्रियान्वयन समय-सीमा के भीतर करें पूर्ण : जिपं सीईओ

★ समय-सीमा की बैठक संपन्न ★ जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण करने के दिए निर्देश ★ अवैध धान पर प्रभावी रोक लगाना प्रशासन की प्राथमिकता

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ श्रीमती तोमर ने सुशासन सप्ताह, धान खरीदी, स्वास्थ्य, पीएम जनमन, राजस्व प्रकरणों सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति लाने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तोमर ने 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित हो रहे सुशासन सप्ताह-प्रशासन गांव की ओर अभियान के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अधिक से अधिक जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने प्राप्त आवेदनों एवं निराकरण की जानकारी संबंधित ऑनलाइन पोर्टल में अनिवार्य रूप से एंट्री करने के निर्देश भी दिए।

धान खरीदी की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने सुचारू एवं पारदर्शी रूप से धान खरीदी सुनिश्चित करने, अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध धान पर प्रभावी रोक लगाना प्रशासन की प्राथमिकता है, इसके लिए अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर विशेष सतर्कता, सघन जांच तथा अवैध धान परिवहन की प्रत्येक गतिविधि पर निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने धान खरीदी से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सक्रियता, सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए।

पीएम जनमन योजना अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए सभी स्वीकृत गतिविधियों का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ शीघ्र मिल सके।

सीईओ श्रीमती तोमर ने स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए एनआरसी सेंटर के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन कार्ड की प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्ड बनाने एवं वितरण की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने स्वास्थ्य शिविरों की जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने को कहा। उन्होंने दुरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा एवं जनजातीय समुदायों को स्वास्थ्य सहित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तोमर ने राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर समय-सीमा के भीतर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्तीकरण के प्रकरणों के निराकराण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जनदर्शन, जनशिकायत एवं जनचौपाल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा कर समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला पंचायत सीईओ ने कोषालयीन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में भी जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, चेतन बोरघरिया, अभिषेक गुप्ता, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रेलवे संघर्ष समिति ने सरगुजा सांसद को दिया ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। रेलवे स्टेशन बिश्रामपुर में अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 22407/22408 के ठहराव को लेकर आज बिश्रामपुर रेलवे संघर्ष समिति द्वारा सरगुजा सांसद चिंतामणि महराज को ज्ञापन सौंपा गया है। मंगलवार को रेल संघर्ष समिति बिश्रामपुर ने सरगुजा सांसद को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बिश्रामपुर स्टेशन न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि यह सरगुजा संभाग का एकमात्र गुड्स शेड भी है, जहां प्रतिदिन भारी मात्रा में आवश्यक सामग्रियों की रेकें आती-जाती हैं। यह स्टेशन कभी पूरे संभाग का अंतिम स्टेशन हुआ करता था, जिसके वर्षों बाद अंबिकापुर तक रेल लाइन का विस्तार हुआ। बावजूद इसके बिश्रामपुर स्टेशन को आज भी उचित महत्व नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में संचालित कोयला खदानों में कार्यरत देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों कर्मचारी बिश्रामपुर व आसपास में निवासरत हैं।

दिल्ली सहित उत्तर भारत, मध्य भारत व अन्य राज्यों के लिए नियमित रेल सेवा की आवश्यकता सबसे अधिक इन्हीं को पड़ती है। अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस सरगुजा को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली इकलौती सुविधा है, ऐसे में इसका बिश्रामपुर में ठहराव न होना स्थानीय जनता के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। ज्ञापन सौंपने वालों में समिति के प्रदीप गर्ग, पूर्व नपं बिश्रामपुर अध्यक्ष राजेश यादव, अशोक अग्रवाल शोक्की, विवेक जायसवाल, अंशुमान तिवारी व अन्य उपस्थित थे।

हिंदू महासंगम में मुख्य वक्ता ने दिया पंच परिवर्तन का संदेश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर उपखंड लटोरी में हिंदू महासंगम का आयोजन किया गया। महासंगम में लटोरी मंडल अंतर्गत आने वाले सभी 18 गांवों से बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोकनृत्य सुआ, कर्मा एवं शैला ने समां बांध दिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करना एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का संदेश देना रहा। मुख्य वक्ता के रूप में सिद्धिविनायक पांडेय प्रांत बौद्धिक टोली के गीत विधा प्रमुख ने हिंदू समाज को एकजुट रहने एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाए जा रहे पंच परिवर्तन के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए ऊंच-नीच, भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करने, पर्यावरण संरक्षण तथा अधिक से अधिक स्वदेशी एवं देसी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया।

कार्यक्रम में मंचासीन भुवनेश्वर सिंह, सुखदेव मुनि एवं काशी प्रसाद जायसवाल थे। महासंगम में लटोरी मंडल की माताएं-बहनें एवं वरिष्ठ नागरिकों की अच्छी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठजनों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।

महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा के लिए शासन का ऐतिहासिक फैसला

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। छत्तीसगढ़ की नगरीय राजनीति में एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ सामने आया है। महिला सशक्तिकरण को केवल कागजों तक सीमित न रखते हुए, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वर्षों से चली आ रही प्रॉक्सी राजनीति पर करारा प्रहार किया है। शासन ने सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र, भाई या अन्य पारिवारिक रिश्तेदार किसी भी रूप में प्रॉक्सी प्रतिनिधि या लायजन पर्सन की भूमिका में नजर नहीं आएंगे। यह निर्देश मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को जारी किया गया है। इसका उद्देश्य महिला आरक्षण की भावना को वास्तविक अर्थों में लागू करना और महिला नेतृत्व को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिलाना है।

ज्ञात हो कि नगरीय निकायों में यह आम शिकायत रही है कि महिला जनप्रतिनिधि नाम मात्र की होती हैं, जबकि उनके स्थान पर परिवार के पुरुष सदस्य बैठकों में भाग लेते हैं, अधिकारियों से संवाद करते हैं और विकास कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं।

शासन ने बताया कि वर्ष 2010 में ही इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन बावजूद इसके कई निकायों में नियमों की अनदेखी होती रही है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद शासन ने इसे और सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने पत्र 29 अक्टूबर 2025 में इस व्यवस्था को संविधान विरोधी करार दिया है। आयोग के अनुसार महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके रिश्तेदारों की भूमिका निभाना अनुच्छेद 14, 15(3), 21 गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। आयोग ने इसे महिला अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों दोनों के लिए घातक बताया है। बताया जा रहा है कि मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकार की प्रॉक्सी नियुक्तियों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है। जारी आदेश में अब नियमों की अनदेखी करने वालों पर प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि आपराधिक कार्रवाई भी संभव है।शासन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकाय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने नगरीय निकायों में नामांकित जनप्रतिनिधियों की तत्काल समीक्षा करें। जहां भी महिला जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक रिश्तेदार प्रॉक्सी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त पाए जाएं। वहां सांसद एवं विधायक को अवगत कराते हुए मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुसार नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें।

इस आदेश के बाद कई नगरीय निकायों में बड़े प्रशासनिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है।राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नगरीय राजनीति में महिला नेतृत्व को वास्तविक ताकत देगा। अब महिला जनप्रतिनिधि स्वयं बैठकों में हिस्सा लेंगी, योजनाओं पर निर्णय करेंगी और जनता के सामने जवाबदेह होंगी। इससे न केवल लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नगरीय निकायों में इस निर्देश का कितनी सख्ती से पालन करते हैं। नगरीय राजनीति में अब नाम की महिला, काम का पुरुष वाली व्यवस्था के दिन लदने लगे हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र में किया गया किसान दिवस का आयोजन

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। किसान दिवस पर कृषि विज्ञान केन्द्र में किसानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों से सीधा संवाद किया गया तथा किसानों को समृद्ध और सुदृढ करने, आर्थिक लाभ में वृद्धि तथा विभागीय योजनाओं के लाभ लेने हेतु जागरूक किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण की व्यवस्था कृषि विज्ञान केन्द्र में किया गया। कार्यक्रम के पश्चात किसान दिवस के अवसर पर कृषकों के लिए एक दिवसीय दलहन एवं तिलहन उत्पादन की उन्नत तकनीक, प्राकृतिक खेती विषय में कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष श्री राम नरेश कुशवाहा, श्री गोपाल कृष्ण मिश्रा वरिष्ठ कार्यकारणी सदस्य एवं गणमान्य नागरिक, श्री विकास मण्डल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। किसान दिवस में आयोजित कार्यशाला में कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. गौरव कांत निगम द्वारा कृषि में नवाचार को बढावा देने हेतु दलहन एवं तिलहन फसलों की बढ़ती मांग को देखते हुये कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त उन्नत किस्म की दलहन एवं तिलहन बीजो का उपयोग तथा वैज्ञानिक विधि से फसल की खेती से होने वाले आर्थिक लाभ एवं उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकि विधि की विस्तृत जानकारी दी गई। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रो की भूमिका तथा उनके उपयोग की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान वर्तमान समय में किसानों द्वारा पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभाव (जैसे मिट्टी की उर्वरता में कमी, वायु प्रदूषण, लाभकारी जीवाणु का नष्ट होना) की भी जानकारी दी गई।

कृषि वैज्ञानिक श्रीमती आरती कुजूर द्वारा प्राकृतिक खेती के लाभ महत्व एवं सम्भावना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के अनियंत्रित उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। डॉ. अनुप कुमार पॉल द्वारा (ऑयल पाम) के उत्पादन की उन्नत तकनीकी तथा दलहन एवं तिलहन फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन एवं मृदा परीक्षण हेतु किसानों को जागरूक किया गया।

कृषि वैज्ञानिक देवेन्द्र कुमार द्वारा किसानों को मछली पालन हेतु आधारभूत जानकारी प्रदान किया गया साथ ही इंडियन मेजर कार्प एवं एग्जॉटिक कार्प मछली पालन हेतु तकनीकी जानकारी एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री अनिल कुमार सोनपाकर द्वारा प्राकृतिक खेती के माध्यम से फसल कीट प्रबंधन की जानकारी दी गई। कृषि अधिकारी द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी साझा की गई। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष ने किसानों को अन्नदाता के रूप मे कार्य करने हेतु सराहना करते हुए कहा कि कृषकों द्वारा निरंतर हमारी कृषि को बढावा दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने केंचुआ खाद के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य एवं बंजर होते खेत को बचाने हेतु सुझाव, प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर एवं गोमूत्र के लाभ एवं उपयोगिता के बारे में कृषकों को सुझाव दिया गया। इस दौरान कृषको ने कृषि विज्ञान केन्द्र में स्थापित विभिन्न इकाईयों जैसे (मुर्गीपालन इकाई, ग्रीन शेड नेट इकाई, बायो फ्लॉक इकाई, ऑयल पाम इकाई) आदि का भ्रमण किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में कृषको को फलदार पौधा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कृषक सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले के धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों की उपज का समर्थन मूल्य पर खरीदी का सिलसिला सुचारू रूप से जारी है। शासन की यह पहल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो रही है। इस व्यवस्था के चलते किसान अपने जीवन स्तर में सुधार कर अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो रहे हैं।

विकासखंड बलरामपुर के ग्राम लुरगी के किसान श्री देव कुमार गुप्ता ने पस्ता धान उपार्जन केंद्र में 106 क्विंटल धान का विक्रय किया। श्री देव कुमार के पास 06 एकड़ खेती योग्य जमीन है, जिसमें वे परंपरागत खेती करते हुए धान की फसल उगाते हैं। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा 3100 रूपए प्रति क्विंटल दर से खरीदी किए जाने से उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है। श्री देव कुमार ने कहा कि इस वर्ष धान बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग वे घर के आवश्यक खर्च, बच्चों की शिक्षा और बचत के लिए करेंगे। श्री देव कहते है कि शासन की समर्थन मूल्य धान खरीदी नीति से किसान की मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है जो कि किसानों की खुशहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने पारदर्शी सुव्यवस्थित धान खरीदी के लिए शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया है।

80 बोरी अवैध धान सहित पिकअप वाहन जब्त

कलेक्टर के मार्गदर्शन में धान खरीदी सीजन में बिचौलियों द्वारा पड़ोसी राज्यों से अवैध धान खपाने की कोशिशों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन की इसी सतर्कता के कारण विकासखंड रामचन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम टाटीआथर में एक पिकअप वाहन की जांच की गई, जिसमें लगभग 80 बोरी अवैध धान पाया गया। संयुक्त टीम ने तत्काल मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान और वाहन को जब्त किया।

जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक पश्चात् जनदर्शन का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने जनदर्शन में अपनी समस्याओं को जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के समक्ष रखा। उन्होंने आमजनों से प्राप्त शिकायत एवं समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुन जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

जन्मदिन पर अनमोल उपहार, हर्ष दनौदीया ने मरणोत्तर आंखें दान कर जीवनों को रोशन करने का लिया संकल्प

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जन्मदिन के खास मौके पर जहां लोग केक काटने और पार्टी करने में व्यस्त रहते हैं, वहीं युवा हर्ष दनौदीया ने अपने जन्मदिन को एक नेक संदेश के रूप में चिन्हित कर दिया। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के निस्वार्थ सेवा कार्यों से प्रेरित होकर हर्ष ने मरणोपरांत अपनी दोनों आंखें दान करने का संकल्प लिया है। यह पहल न केवल अंगदान के महत्व को रेखांकित करती है, बल्कि समाज में मानवता की मिसाल भी पेश करती है। गौरतलब है कि हर्ष दनौदीया, जो विश्रामपुर के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि रेडक्रॉस सोसाइटी के जरिए जरूरतमंदों की

मदद देखने के बाद उनके मन में यह विचार आया। मेरा जन्मदिन सिर्फ मेरी खुशी का दिन नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने का अवसर भी है ।मरणोत्तर मेरी आंखें किसी अंधे व्यक्ति को नई जिंदगी देंगी, यही मेरी सबसे बड़ी भेंट होगी, हर्ष ने भावुक होकर कहा। उनका यह संकल्प जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में दर्ज कराया गया, इसके बाद तमाम प्रक्रियाओं को पूर्ण करने पर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है यह कदम-डॉ. पैकरा

इस नेक कार्य की सराहना करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कपिल देव पैकरा और सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम ने हर्ष को प्रमाण पत्र सौंपा। डॉ. पैकरा ने कहा, हर्ष का यह कदम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंगदान जैसे संकल्प से हम न केवल जीवन बचाते हैं, बल्कि एक सकारात्मक सोच का प्रसार भी करते हैं ।जिला प्रशासन ऐसी पहलों को हमेशा प्रोत्साहित करेगा।

स्कूल और कॉलेजों में चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान

सिविल सर्जन डॉ. मरकाम ने जोर देकर कहा कि अंगदान का संदेश फैलाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिशा में आगे आएं और उनके महादान से किसी और का जीवन भी प्रकाशमान हो सके।

हर्ष जैसे युवा हमारी प्रेरणा- अग्रवाल

जिला रेडक्रॉस सोसाइटी ने भी हर्ष की इस पहल की प्रशंसा की। सोसाइटी के चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल ने बधाई देते हुए कहा, रेडक्रॉस का मिशन ही सेवा और दान है। हर्ष जैसे युवा हमारी प्रेरणा हैं। हम उनके इस संकल्प को सोसाइटी के सभी कार्यक्रमों में हाइलाइट करेंगे। वाइस चेयरमैन ओंकार पांडेय ने इसे 'जीवन दान का संकल्प' करार देते हुए कहा कि इससे समाज में अंगदान को लेकर जो हिचकिचाहट है, वह दूर होगी। कोषाध्यक्ष श्रवण जैन ने भी हर्ष को शुभकामनाएं दीं और कहा कि सोसाइटी जल्द ही अंगदान पंजीकरण शिविर आयोजित करेगी। वहीं, जिला प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्य अजय अग्रवाल अज्जू ने इसे 'युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग' बताते हुए युवाओं से अपील की कि वे भी ऐसे संकल्प लें।

रामानुजनगर में 25 दिसंबर को हिंदू सम्मेलन का आयोजन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। हिन्दू जनजागरण समिति के तत्वावधान में आगामी 25 दिसंबर को रामानुजनगर हाईस्कूल ग्राउंड में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में सहभागिता हेतु क्षेत्र के समस्त नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में रामानुजनगर मंडल अंतर्गत 33 समाजों के समाज प्रमुखों एवं उनके प्रतिनिधियों को एक मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न समाजों को एक सूत्र में बाँधते हुए सामाजिक समरसता, आपसी सहयोग, संवाद और एकता को सुदृढ़ करना है। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राजकुमार चंद्रा जी, प्रांत धर्मजागरण संयोजक होंगे। वे अपने उद्बोधन में समाज में व्याप्त चुनौतियों, सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता तथा उनके समाधान पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

कलेक्टर ने दिए गति के साथ गुणवत्ता युक्त निराकरण के निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गुणवत्ता युक्त प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता से प्रगति लाएं। समय सीमा में प्रकरण के निराकरण से आम जनता को संतोष मिलता है। इस हेतु लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करें। कलेक्टर ने तहसीलवार अविवादित/ विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, ई-कोर्ट प्रकरण सहित सभी राजस्व प्रकरणों की प्रगति पर समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने विवादित/ अविवादित नामांतरण के आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी तहसीलदारों को लंबित प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा बटांकन कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को सक्रिय होकर तत्परता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा सभी एसडीएम को इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने निर्देशित किया। उन्होंने नक्शा बटांकन, आधार सीडिंग, अभिलेख शुद्धता, प्राकृतिक आपदा के लंबित प्रकरण, वन अधिकार पट्टा सहित राजस्व मामलों की अन्य प्रकरणों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिले के विकासखंड एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डोर टू डोर बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन के दिशा निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.के.डी. पैकरा एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. हर्षवर्धन शर्मा के मार्गदर्शन में समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी के कुशल नेतृत्व में विकासखंड के सभी क्षेत्रों में पल्स पोलियो अभियान के तहत डोर टू डोर बच्चों को 0 से 5 साल के सभी बच्चों को पल्स पोलियो अभियान की दो बूंद खुराक दिलाई जा रही हैं। विकासखंड ओडगी बिहारपुर के सुदूर अंचल खोहिर, रामगढ़, बैजनपाठ, लुल, छतरंग, खोंड, में वैक्सीन करियर पड़कर पैदल चलकर मितानिन कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कार्यकताओं के द्वारा बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही हैं। जिसमें सभी आम नागरिक जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन और जनता जर्नादनों का आभार प्रदर्शन व्यक्त किया जा रहा है इस हेतु सभी से अपील किया जा रहा है कि शत प्रतिशत बच्चों का को पोलियो की दो बूंद पिलाई जानी आवश्यक है। पल्स पोलियो अभियान के दूसरे दिन घर-घर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। जिसमें कुल दवा पिलाई जाने वाली बच्चों की संख्या 104660 जिसमें 0 से 5 साल के बच्चों प्रथम दिवस में 95382, दूसरे दिवस घर-घर जाकर 6106 कुल 101488 बच्चों को दवा पिलाकर जिले ने 96.97 प्रतिशत हासिल किये है। शेष बचे हुए बच्चों को तीसरे दिन घर घर जाकर दवा पीला लिया जाएगा ।विकासखंड प्रतापपुर में कुल पिलाया जाने वाली बच्चों की संख्या 18964 मे से 18416 बच्चों को दवा पिलाकर 97.11 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। विकासखंड भैयाथान में कुल पिलाया जाने वाली बच्चों की संख्या 18084 में से 17572 बच्चों को दवा पिलाकर 97.17 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है।

विकासखंड ओडगी में कुल पिलाया जाने वाली बच्चों की संख्या 10955 मे से 10790 बच्चों को दवा पिलाकर 98.19 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। विकासखंड प्रेमनगर में कुल पिलाया जाने वाली बच्चों की संख्या 8351 मे से 8200 बच्चों को दवा पिलाकर 98.19 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है।

16 जनवरी को अंबिकापुर में हसदेव बचाओ संघर्ष समिति का विशाल आंदोलन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। भारतेंदु भवन, में हसदेव बचाओ संघर्ष समिति, सरगुजा के बैनर तले खनन एवं उद्योग प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की बैठक आयोजित हुई जिसमे कोरबा, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, रायगढ़, राजनादगांव आदि जिलों से आंदोलन के संघर्षशील साथी शामिल हुए। विभिन्न आंदोलन के साथियों ने कहा कि सरकारें वैधानिक ग्रामसभाओं के द्वारा लिए निर्णय, सहमति/परामर्श के विरूद्ध जाकर दमनात्मक कार्यवाही करते हुए फर्जी ग्रामसभा, दाबावपूर्ण कार्यवाही कर ग्राम सभा का आयोजन करके जंगल-जमीन से लोगों को बेदखल कर रही हैं। राज्य सरकार जनता के हितों के बजाए अदानी जैसे कारपोरेट के एजेंट की तरह काम कर रही है। बैठक को संबोधित करते हुए त्रिभुवन सिंह ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ विस्थापित होने वाले लोगों एवं प्रभावित गांव की ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की है। यदि इसी तरह जंगल कटाई, अनियंत्रित खनन और औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित होतीं रही तो छत्तीसगढ़ की नदियाँ सूख जायेंगी, बाँधों का जल क्षेत्र कम होगा जल संकट बढ़ेगा, जंगल विहीन प्रदेश आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक भी नहीं बचेगा, इसलिए पर्यावरणीय क्षति से बचने सभी को एकजुट होकर सभी मोर्चे पर साथ ही विधि सम्मत संघर्ष भी जारी रखना होगा। हसदेव संघर्ष समिति से रामलाल करियाम एवं मुनेश्वर पोर्ते ने कहा कि हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा राज्य और केंद्र सरकार ने किया है। फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव बनाकर कंपनी ने वन स्वीकृति हासिल की है। इसी फर्जी वन स्वीकृति के आधार पर पुलिस लगाकर दमन करके हमारे जंगल को काटा जा रहा है। आंदोलन के मुखिया साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्रामसभा के फर्जी प्रस्ताव बनाने वाले अधिकारी और कंपनी पर कार्यवाही की जगह ग्रामीणों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के साथी आलोक शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकारें धान के कटोरा छत्तीसगढ़ को खदानों का छत्तीसगढ़ बना रही है। सरकार संविधान और कानून से नहीं बल्कि अदानी जैसे पूंजीपतियों के कार्यालय से चल रही है। इस विनाश को रोका नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियाँ हमे कभी माफ नहीं करेंगी । खाद्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने कहा कि ये लड़ाई पर्यावरण को बचाने की भी है और छत्तीसगढ़ के जनजीवन को भी संकट से बचाने की है इसमें शहर के लोग भी साथ हैं। जिस धरती ने हमे सब कुछ दिया है उसके विनाश पर हम चुप नहीं रह सकतें संघर्ष करेंगे। गोष्ठी के अन्त में भानुप्रताप सिंह पूर्व आदिवासी आयोग के अध्यक्ष ने कहा एजुटता के साथ हम सभी को चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू अधिनियमों का खुलकर उलंघन किया जा रहा है जिसका विरोध संभाग स्तर पर किया जावेगा,साथ ही राज्य स्तरीय रूपरेखा तय कर छत्तीसगढ़ में हो रही पर्यावरणीय क्षति को बचाने जन आंदोलन को गति दिया जावेगा। बैठक में सामूहिक निर्णय लिया गया कि आगामी 16 जनवरी को अम्बिकापुर मुख्यालय में हजारों की संख्या में एकजुट होकर रैली और धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

राज्य सरकार तत्काल जंगलों की कटाई बंद कर ग्राम सभाओं के निर्णयों का पालन करें । जबरन भूमि छीनने की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए एवं जहाँ खनन परियोजना पूर्व से संचालित है वहाँ पुनर्वास रोजगार और अधिकतम मुआवजा ब्याज सहित भुगतान के अधिकार को सुनिश्चित करें । पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह सोढ़ी, प्रितपाल सिंह, वेदप्रकाश अग्रवाल, डॉ व्ही के सिंह, डमरू रेड्डी, बाल सिंह, रणविजय सिंह ने पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए आन्दोलन से जुड़े सैकड़ों महिला और पुरुष कार्यकर्ता विचार गोष्ठी में शामिल हुए।

प्रतापपुर तहसील में अभिलेख नकल और जाति निवास प्रमाणपत्र का त्वरित वितरण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सुशासन सप्ताह, प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत तहसील कार्यालय प्रतापपुर में आये आवेदन को संज्ञान में लेकर निस्तारण किया जा रहा है। तहसील कार्यालय द्वारा अभिलेख, नकल एवं जाति-निवास प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। आवेदकों को बिना किसी विलंब के उनके दस्तावेजों की नकल और आवश्यक प्रमाणपत्र जारी कर सौंपे जा रहें हैं। आवेदिका श्रीमती शनिचरी बाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जनदर्शन में आवेदन दिया था। सुशासन सप्ताह के दौरान तहसील प्रशासन ने आवेदिका की समस्या को प्राथमिकता देते हुए तत्काल निराकरण किया। पेंशन योजना के तहत आवेदिका की पेंशन कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। अब आगामी माह से श्रीमती शनिचरी बाई को नियमित पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह पहल सुशासन के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

रेडक्रॉस सोसायटी की कार्यप्रणाली पारदर्शी और लंबित ऑडिट हेतु 3 सदस्यीय जांच दल गठित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां जनसहयोग से संचालित रेडक्रॉस सोसायटी की कार्यप्रणाली को लेकर जिले में चर्चा तेज हो गई है। लंबे समय से ऑडिट नहीं होने और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को लेकर रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल ने कलेक्टर एस जयवर्धन को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने तीन सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन कर दिया है। चेयरमैन श्री अग्रवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि रेडक्रॉस सोसायटी जनसहयोग और सार्वजनिक विश्वास पर आधारित संस्था है, ऐसे में इसके प्रत्येक कार्य, खर्च और निर्णय में पूर्ण

पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले में लंबे समय से सोसायटी का ऑडिट नहीं हो पाया है और बैठकों व खर्चों को लेकर भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। इस विषय को उन्होंने सोसायटी की बैठकों में भी उठाया, ताकि कार्यशैली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। कलेक्टर के निर्देश पर कार्यालय कलेक्टर शिकायत शाखा द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल की अध्यक्षता अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा करेंगे। दल में जिला कोषालय अधिकारी कार्यालय से प्रेमशंकर तिवारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कपिलदेव पैंकरा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जांच दल को रेडक्रॉस सोसायटी के आय-व्यय, अनुदान उपयोग, बैंक खातों तथा लंबित ऑडिट से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी जानकारी सार्वजनिक होने पर जनचर्चाओ में स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकताओं का कहना है कि इससे न केवल रेडक्रॉस सोसायटी में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि भविष्य में जनसहयोग से संचालित संस्थाओं की कार्यशैली को भी अधिक जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत केवरा में सुशासन सप्ताह के भव्य कार्यक्रम में दी गई आवास की चाबी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जरही। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गृहप्रवेश सह उन्मुखीकरणह्व कार्यक्रम का भव्य आयोजन ग्राम पंचायत केवरा के हरार्पारा मोहल्ले में बड़े उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम जनपद अध्यक्ष सुखमनिया आयाम के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रशासन द्वारा आयोजित यह सुशासन सप्ताह कार्यक्रम पारदर्शिता के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और विकास के लिए संकल्पित शासन की एक अभिनव पहल है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न

जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। जनपद पंचायत प्रतापपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2016 से 2025-26 तक कुल 8831 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6122 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 2704 आवास प्रगतिरत हैं। जनपद दृष्टिकोण से केवरा जैसी बड़ी ग्राम पंचायत में सबसे अधिक 233 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 58 पूर्ण हो चुके हैं और 175 आवास निमार्णाधीन हैं।

इसी क्रम में जनपद अध्यक्ष ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाले समय में इस योजना के तहत ग्रामीण कामगारों और मजदूरों को अधिक सुविधाओं के साथ बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। डबल इंजन सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से ग्रामीण श्रमिकों के आर्थिक स्तर को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं प्रतापपुर विधानसभा की चौमुखी विकास यात्रा को लेकर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के अथक प्रयासों की भी सराहना की गई।

ऑडिट हेतु 3 सदस्यीय जांच दल गठित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां जनसहयोग से संचालित रेडक्रॉस सोसायटी की कार्यप्रणाली को लेकर जिले में चर्चा तेज हो गई है। लंबे समय से ऑडिट नहीं होने और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को लेकर रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल ने कलेक्टर एस जयवर्धन को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने तीन सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन कर दिया है। चेयरमैन श्री अग्रवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि रेडक्रॉस सोसायटी जनसहयोग और सार्वजनिक विश्वास पर आधारित संस्था है, ऐसे में इसके प्रत्येक कार्य, खर्च और निर्णय में पूर्ण पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले में लंबे समय से सोसायटी का ऑडिट नहीं हो पाया है और बैठकों व खर्चों को लेकर भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी।

सम्पादकीय

'वीबी-जी राम जी' देगी ग्रामीण जीवन को गति

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत कर ग्रामीण जीवन को मजबूती देने का काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सीधे गांव के लोगों को काम देने की बजाय गांवों की आमदनी बढ़ाना है। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। खेती, पशुपालन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है और गांव को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। यह विधेयक हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून बन गया। इस योजना ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लिया है। मनरेगा अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिन कर दिया गया है। जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है। सरकार इसे ग्रामीण जीवन को मजबूत आधार देने वाला ऐतिहासिक कदम बता रही है। इसके लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कुछ बदल जाएगा। इस योजना को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। इनमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर और मौसमी घटनाओं के लिए विशेष कार्य शामिल हैं। यह अधिनियम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जिसे राज्यों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित और क्रियान्वित किया जाएगा। व्यय-साझेदारी का पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, तथा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण का है। निधि राज्यवार मानकीकृत आवंटनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो नियमों में निर्दिष्ट वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होगी (धाराएं 4(5) एवं 22(4)), जिससे पूर्वानुमेयता, वित्तीय अनुशासन और सुदृढ़ योजना निर्माण सुनिश्चित होगा, साथ ही रोजगार तथा बेरोजगारी भत्ते से संबंधित वैधानिक अधिकारों का पूर्ण संरक्षण बना रहता है। वीबी-जी राम जी कानून लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कानूनी गारंटी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ग्रामीणों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। नए कानून का मकसद केवल रोजगार नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज का समग्र सशक्तिकरण करना है। इसमें समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके और उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। यह कानून महिलाओं, कमजोर वर्गों और जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती प्रदान करेगा। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता कम होगी और विकास का लाभ सभी तक पहुंचेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी। विकास कार्य तेजी से होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार होगा। ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार दिए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो सकेगी। रोजगार बढ़ने से गांवों में आय के साधन मजबूत होंगे और शहरों की ओर पलायन पर भी रोक लगेगी। यह योजना विकसित भारत 2047 के विज़न के पूर्णतः अनुरूप है।

सहकारिता
महेन्द्र तिवारी

भारत टैक्सी से ओला-उबर को चुनौती

भारत टैक्सी का अमूल-आधारित सहकारी मॉडल भारत की ऐप-आधारित टैक्सी अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक नया स्टार्ट-अप नहीं, बल्कि एक वैचारिक हस्तक्षेप के रूप में सामने आ रहा है। पिछले एक दशक में ओला-उबर जैसे प्लेटफॉर्मों ने शहरी मोबिलिटी को तेज़, सुलभ और तकनीक-संचालित बनाया, लेकिन इसके साथ ही गिग-इकोनॉमी का एक ऐसा चेहरा भी उभरा, जिसमें ड्राइवर ऊँचे कमीशन, अस्थिर आय, एल्गोरिद्मिक दंड और सर्ज प्राइसिंग की मार झेलते रहे। यात्रियों को भी कभी-कभी सुविधा के बदले अनियंत्रित किराया और सुरक्षा को लेकर असहजता स्वीकार करनी पड़ी। इसी पृष्ठभूमि में भारत टैक्सी एक ऐसे विकल्प के रूप में प्रस्तुत हो रही है, जो लाभ अधिकतमकरण की जगह सहकार, स्वामित्व और न्याय की भाषा बोलती है।

भारत टैक्सी का मूल विचार अमूल मॉडल से प्रेरित है, हज़ारों छोटे-छोटे हितधारकों को जोड़कर एक बड़ा, भरोसेमंद और सामूहिक ब्रांड खड़ा करना। जिस तरह अमूल ने दूध उत्पादकों को बाज़ार की ताक़त दी, उसी तरह भारत टैक्सी ड्राइवरों को सिर्फ सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि सहकारी संस्था के सदस्य-साझेदार के रूप में देखती है। "सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड" के ज़रिए संचालित यह पहल ड्राइवरों को साझा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, साझा मार्केटिंग और साझा मुनाफे का हिस्सा बनाती है। सहकारिता मंत्रालय के समर्थन और अमूल, इफको, नाबार्ड, एनसीडीसी जैसी संस्थाओं की भागीदारी इसे एक हद तक संस्थागत विश्वसनीयता भी देती है। दिल्ली और सौराष्ट्र क्षेत्र में पायलट के दौरान ही हज़ारों ड्राइवरों के जुड़ने का दावा बताता है कि यह विचार ज़मीन पर कुछ हद तक स्वीकार्यता पा रहा है।

> भारत टैक्सी का मूल विचार अमूल मॉडल से प्रेरित है, हज़ारों छोटे-छोटे हितधारकों को जोड़कर एक बड़ा, भरोसेमंद और सामूहिक ब्रांड खड़ा करना। जिस तरह अमूल ने दूध उत्पादकों को बाज़ार की ताक़त दी, उसी तरह भारत टैक्सी ड्राइवरों को सिर्फ सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि सहकारी संस्था के सदस्य-साझेदार के रूप में देखती है। "सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड" के ज़रिए संचालित यह पहल ड्राइवरों को साझा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, साझा मार्केटिंग और साझा मुनाफे का हिस्सा बनाती है। सहकारिता मंत्रालय के समर्थन और अमूल, इफको, नाबार्ड, एनसीडीसी जैसी संस्थाओं की भागीदारी इसे एक हद तक संस्थागत विश्वसनीयता भी देती है।

ड्राइवर-केंद्रित दृष्टिकोण भारत टैक्सी की सबसे बड़ी विशिष्टता है। मौजूदा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों पर 20 से 30 प्रतिशत तक कमीशन, जटिल इंसेंटिव संरचना और अकसर मनमाने बैन ड्राइवरों की सबसे बड़ी शिकायत रही है। भारत टैक्सी इन शिकायतों का जवाब न्यूनतम या शून्य कमीशन, नाममात्र प्लेटफॉर्म फीस और मुनाफे के सहकारी वितरण के ज़रिए देने का दावा करती है। प्रति राइड मिलने वाली आय का बड़ा हिस्सा सीधे ड्राइवर तक पहुँचना, और अतिरिक्त अधिशेष का सदस्य-लाभांश के रूप में लौटना, इस मॉडल को रोज़गार से आगे बढ़ाकर साझा स्वामित्व की दिशा में ले जाता है। प्रतीकात्मक रूप से ड्राइवरों को "सारथी" कहा जाना भी इसी सोच को रेखांकित करता है कि वे सिर्फ ऐप पर लॉग-इन करने वाले गुमनाम कर्मी नहीं, बल्कि नीति और दिशा तय करने वाले भागीदार हैं। यात्रियों के लिए भारत टैक्सी का आकर्षण पारदर्शिता और स्थिरता में निहित है। सर्ज प्राइसिंग पर रोक और पहले से तय किराया-ब्रैकेट इस वादे के साथ आते हैं कि पीक ऑवर, बारिश या किसी आपात स्थिति में किराया अचानक कई गुना नहीं बढ़ेगा। न्यूनतम किराया, प्रति किलोमीटर दर और दूरी के हिसाब से घटती कीमतें एक ऐसे ढांचे का संकेत देती हैं जिसमें सेवा को सार्वजनिक उपयोगिता के करीब लाने की कोशिश है, न कि केवल अधिकतम मुनाफे का साधन बनाने की। मल्टीलिंगुअल इंटरफेस, रियल-टाइम ट्रैकिंग, 24x7 कस्टमर सपोर्ट और भविष्य में मेट्रो जैसे ट्रांजिट सिस्टम से इंटीग्रेशन का वादा यह दिखाता है कि यह पहल तकनीकी अनुभव में निजी कंपनियों से पीछे नहीं रहना चाहती। फिर भी, इस सहकारी सपने के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। तकनीकी स्तर पर ओला-उबर जैसे दिग्गजों के पास वर्षों का डेटा, परिष्कृत एल्गोरिद्म और विशाल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर है। दो मिनट के भीतर पिक-अप, कम कैंसिलेशन और निर्बाध ऐप अनुभव देना केवल विचारधारा से संभव नहीं, इसके लिए भारी तकनीकी निवेश और दक्ष प्रबंधन चाहिए।

जैसे-जैसे भारत टैक्सी अधिक शहरों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलेगी, सहकारी शासन की जटिलताएँ भी बढ़ेंगी—निर्णय-प्रक्रिया की गति, स्थानीय हितों का टकराव और पेशेवर प्रबंधन व सदस्य-लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा। एक और बड़ी बाधा उपभोक्ता आदतों की है। ओला-उबर अब सिर्फ सेवाएँ नहीं, बल्कि शहरी जीवनशैली का हिस्सा बन चुके हैं। उनके ऐप खोलना, किराया स्वीकार करना और यात्रा शुरू करना एक स्वाभाविक क्रिया बन गई है। भारत टैक्सी को इस आदत को तोड़ने के लिए नैतिक अपील से आगे बढ़कर लगातार बेहतर, भरोसेमंद और सहज अनुभव देना होगा। यदि सेवा में देरी, ड्राइवर उपलब्धता की कमी या तकनीकी खामियाँ रहीं, तो सहकारी विचार का आकर्षण जल्दी फीका पड़ सकता है।

इसके बावजूद भारत टैक्सी का महत्व उसके तत्काल व्यावसायिक भविष्य से कहीं बड़ा है। यह पहल यह प्रश्न उठाती है कि क्या प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से वेंचर-कैपिटल संचालित, प्रॉफिट-मैक्सिमाइजिंग मॉडल तक सीमित रहेगी, या उसमें सहकारी, श्रमिक-केंद्रित विकल्पों के लिए भी जगह बन सकती है। यदि यह प्रयोग सफल होता है और ड्राइवरों की आय व गरिमा में वास्तविक सुधार लाता है, तो यह उदाहरण फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और अन्य गिग-आधारित क्षेत्रों में भी दोहराया जा सकता है। और यदि यह आंशिक या सीमित स्तर पर ही टिक पाता है, तब भी यह बहस को मजबूर करेगा कि तकनीक का इस्तेमाल केवल पूँजी के हित में हो या समाज के व्यापक हित में।

अंततः भारत टैक्सी को एक प्रयोग के रूप में देखना अधिक यथार्थवादी होगा। एक ऐसा प्रयोग जिसमें सरकारी-सहकारी समर्थन और सामूहिक स्वामित्व की ताक़त है, लेकिन बाज़ार की प्रतिस्पर्धा और तकनीकी चुनौतियों का दबाव भी उतना ही वास्तविक है। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि टैक्सियों का यह "अमूल मॉडल" भारतीय मोबिलिटी इकोसिस्टम में एक नई धारा बनता है या समानांतर, सीमित-कक्षा का विकल्प बनकर रह जाता है। पर इतना स्पष्ट है कि इसने प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था की दिशा पर एक ज़रूरी और समयोचित सवाल खड़ा कर दिया है और यही किसी भी संपादकीय रूप से महत्वपूर्ण पहल की असली कसौटी है। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर सहित अन्य अधिकारियों ने इस योजना का समर्थन किया है और इसे देश में एक स्थानीय और पारदर्शी राइड-हेलिंग ऑप्शन के रूप में पेश किया है। कहा गया है कि इस पहल से ना केवल ड्राइवरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि भारतीय राइड-शेयरिंग उद्योग में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गणित दिवस

बाल मुकुन्द ओझा

गणितीय जगत के बेजोड़ नक्षत्र थे रामानुजन

आज 22 दिसंबर के दिन हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है जिनका जन्म 22 दिसंबर, 1887 को तमिलनाडु राज्य के इरोड नामक स्थान पर हुआ था। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने 100 साल पहले गणित की जो गुत्थियां सुलझाई थीं, वह आज भी विज्ञान की दुनिया को हैरान कर रही हैं। रामानुजन को आधुनिक काल के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। उन्होंने अपने जीवनकाल में गणित के विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिया। रामानुजन को गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था इसके बावजूद इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से ना केवल गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए अपितु भारत को वैश्विक स्तर पर गौरव प्रदान कराने का भी काम किया था। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत और गणित का रिश्ता बहुत अटूट रहा है। माना जाता है कि भारत ही वह देश है जिसने पूरी दुनिया को गणित के सबसे महत्वपूर्ण अंक 'शून्य', नकारात्मक संख्या, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति जैसे विषयों से अवगत कराया था। ऐसा देखा गया है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी गणित के नाम से अपने पैर पीछे खींच लेती है। हम अपना

हर छोटा मोटा हिसाब आजकल मोबाइल पर करने लगे हैं। आज भी पुरानी पीढ़ी के लोग जोड़ बाकी अँगुलियों पर करते हैं और नई पीढ़ी के युवा मोबाइल का सहारा लेते हैं। नई तकनीक ने हालांकि गणित को हल करने में सरलता कर दी है। इसके बावजूद गणित के प्रति हमारा रवैया सकारात्मक नहीं है। लोगों में गणित के प्रति जागरूकता और उत्साह उत्पन्न करने के लिए इस दिवस को मानते हैं। इस दिन गणित के शिक्षकों और छात्रों को इस विषय को आसान बनाने और लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर 2012 को चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगाठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीनिवास रामानुजन को श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष और साथ ही उनके जन्मदिन के अवसर पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। तभी से 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से रामानुजन को याद किया जाता है और गणित के महतत्व की जानकारी दी जाती है। रामानुजन को बचपन से ही गणित में काफी रुचि थी। उन्होंने किसी भी तरह की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ऐसी-ऐसी खोजें कीं कि बड़े-बड़े गणितज्ञ हतप्रभ रह गए। रामानुजन ने 12 साल की उम्र में त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी और बिना किसी की सहायता के खुद से कई प्रमेय भी विकसित किए। उनका यह कार्य ऐतिहासिक माना गया था। रामानुजन की प्रतिभा का पता इसी से लगाया जा सकता है कि जब वह सातवीं कक्षा में पढ़ते थे तो उसी समय ये बी. ए. के छात्रों को गणित पढ़ाया करते थे। लोनी के द्वारा प्रसिद्ध त्रिकोणमिति जिसे हल करने में बड़े-बड़े गणितज्ञ असफल हो जाया करते थे, मगर इन्होंने अपनी मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही हल करके अपनी प्रतिभा को प्रमाणित कर दिया था। उनके बारे में यह कहा जाता था कि वे गणित के किसी भी प्रश्न को सबसे अधिक आसान तरीके से हल कर सकते थे। उनकी इसी विलक्षण प्रतिभा ने इनको विश्व में गणित का गुरु होने का दर्जा दिलाया था। गणित के क्षेत्र में किए गए कार्यों की वजह से इनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया गया है। इन्होंने अपने कार्यों के द्वारा भारत के सम्मान में भी चार चाँद लगाए। टीबी की बीमारी की वजह से रामानुजन का 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गावत संतत संभु भवानी

संकलित
दर्शन

शिव वो हैं, जो सब कुछ सहजता के साथ लेते हैं। शिव भक्ति का एक अर्थ यह भी है कि सब कुछ सहजता के साथ किया जाए और सब कुछ सहजता के साथ लिया जाए। व्यक्ति मुस्कुराए तो सहजता के साथ और रोये तो भी सहजता के साथ। भगवान शिव इतने सहज हैं कि देवों के देव होने के बावजूद वो नाचते भी हैं, गाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण ने गीता गाई, तुलसीदास श्रीरामचरितमानस गाते हैं, वैसे ही भगवान शिव भी गाते हैं। भगवान शिव ने माथे पर वक्रचंद्र को धारण किया है। यह एक संकेत है कि तुम में चाहे कितनी ही वक्रता हो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। सब कुछ स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। कोई कैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लिया जाए। हम स्वीकार करने के बजाय दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं और यह काम कभी हो नहीं पाता। इससे अकारण ही संघर्ष पैदा होता है। शिव सहज भी हैं और सबको स्वीकार भी करते हैं, साथ ही उनमें संतोष भी है। सावन के इन दिनों में शिव की भक्ति करते हुए हम उनकी तरह संतोषी बनना भी सीखें। मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, प्रमादी नहीं। शास्त्रों में प्रमाद को मृत्यु बताया गया है। लेकिन शिवजी की तरह संतुलन रखना भी हमें आना चाहिए। शिव परिवार में वाहन के रूप में मोर भी है, चूहा भी है, बैल भी है और शेर भी है। सांप भी शिव के साथ रहते हैं। ये सब एक-दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन परिवार में सब मिल-जुल कर रहते हैं। सबके बीच संतुलन बनाकर भगवान महादेव चलते हैं।

मानवता भीतर के संस्कारों से पनपती है

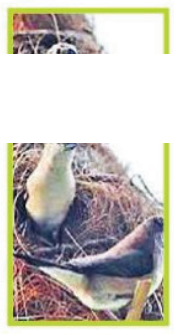

संकलित
प्रेरणा

टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मसूरी जा रहे थे। परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से निकलते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ों पर गौरैया के कई सुन्दर घोंसले बने हुए हैं। यह देखते ही उनकी पत्नी ने अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए गौरैया के दो घोंसले लेने की इच्छा व्यक्त की तो उनके साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक छोटे से लड़के को बुलाया, जो वहां मवेशियों को चरा रहा था। उसे पेड़ों से तोड़ कर दो गौरैया के घोंसले लाने के लिए कहा। लडके ने इंकार में सर हिला दिया। शेषन ने इसके लिए लड़के को 10 रुपए देने की पेशकश की। फिर भी लड़के के इनकार करने पर शेषन ने बढ़ा कर 50 रुपए देने की पेशकश की। फिर भी लड़के ने हामी नहीं भरी। पुलिस ने तब लड़के को धमकी दी और उसे बताया कि साहब जज हैं और तुझे जेल में भी डलवा सकते हैं। गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लड़का तब श्रीमती और शेषन के पास गया और कहा- साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन घोंसलों में गौरैया के छोटे बच्चे हैं अगर मैं आपको दो घोंसले दूं, तो जो गौरैया अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बाहर गई हुई है, जब वह वापस आएगी और बच्चों को नहीं देखेगी तो बहुत दुःखी होगी जिसका पाप मैं नहीं ले सकता। यह सुनकर टीएन शेषन दंग रह गए। शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है: मेरी स्थिति, शक्ति और आईएएस की डिग्री सिर्फ उस छोटे, अनपढ़, मवेशी चराने वाले लड़के द्वारा बोले गए शब्दों के सामने पिघल गई।

पराजय के भय से रचा गया ठाकरे बंधुओं का भय-संगम नाटक फ्लॉप होगा

भाजपा मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन का जोरदार हमला

सूर्यप्रकाश दुबे

आगामी महानगरपालिका चुनावों में पराजय की आशंका के कारण ही ठाकरे बंधु एक साथ आकर 'प्रीति-संगम' नहीं, बल्कि 'भय-संगम' का नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। मतदाता इस 'भय-संगम' के प्रयोग को फ्लॉप कर देंगे, ऐसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन ने उबाठा-मनसे गठबंधन का मजाक उड़ाया। वे सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। श्री. बन ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कभी अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था, मनसे पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया था और आज पराजय के डर से उसी भाई के लिए झूठी प्रीति दिखा रहे हैं। इस अवसर पर श्री. बन ने कहा कि जब राज ठाकरे 100 सीटों की मांग कर रहे हैं, तब उबाठा गुट मनसे को केवल 60 सीटें देकर उन्हें बहलाने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में देश और राज्य में हो रही विकास की तेज रफ्तार मतदाताओं के सामने है। इसलिए ठाकरे बंधुओं के इस भय-संगम नाटक का चाहे जितना ढोल पीटा जाए, यह नाटक मंच पर आने से पहले ही गिर जाएगा, यह निश्चित है। महायुति का प्रयोग हाउसफुल रहेगा और मुंबई सहित सभी महानगरपालिका चुनावों में भाजपाझमहायुति का ही परचम लहराएगा, ऐसा विश्वास भी श्री. बन ने व्यक्त किया। नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा द्वारा पैसे की बौछार किए जाने के राउत के आरोपों पर कड़ा प्रहार करते हुए श्री. बन ने चुनौती दी कि ठोस सबूत दें, अन्यथा निरर्थक बयानबाजी बंद करें। भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त राउत किस मुँह से यह आरोप करते हैं, ऐसे कड़े शब्दों में उन्होंने राउत को सुनाया।

महापालिका चुनावों में भी देवेंद्र फडणवीस ही धुरंधर झ उद्धव ठाकरे रहमान डकैत

नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों को करारी शिकस्त दी है। नगरपालिकाओं के बाद अब महानगरपालिका चुनावों में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही धुरंधर सिद्ध होंगे। छत्रपति संभाजीनगर के नामांतरण के विरोध में याचिका दायर करने वालों को उबाठा गुट में शामिल कर लेने के कारण उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और राउत ही रहमान डकैत हैं, ऐसा उन्होंने कहा। नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों में धुरंधर कौन है, इस पर मतदाताओं ने ही मुहर लगा दी है, ऐसा भी उन्होंने कहा।

रोहित पवार पर श्री. बन का पलटवार

कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कहने वाले हास्यास्पद आरोप पर श्री. बन ने रोहित पवार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की घटक पार्टी कांग्रेस को, पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तुलना में तीन गुना अधिक सीटें मिली हैं, इसी ईर्ष्या के कारण रोहित ऐसे आरोप लगा रहे हैं।

निलेश राणे और महायुति की एकजुटता बरकरार

निलेश राणे महायुति का ही हिस्सा हैं। सिंधुदुर्ग में कुछ स्थानों पर गठबंधन नहीं हो सका, इसलिए अलग-अलग चुनाव लड़े गए। कुछ मतभेद हुए, लेकिन हमारे बीच कोई मनभेद नहीं है, यह स्पष्टता श्री. बन ने दी।

चुनाव जीतने पर जुलूस और हारने पर राउत का रोना

जैसे छोटा बच्चा जीतने पर उछलता-कूदता है और हारने पर रोता है, वैसे ही चुनाव हारने के बाद राउत का रोना शुरू हो जाता है। बचकानेपन के कारण ही राउत ने बिहार और तेलंगाना का मुद्दा उठाया है, ऐसी तीखी आलोचना श्री. बन ने की। घर में बैठने वालों को मतदाताओं ने घर बैठा दिया और दिन-रात विकास करने वालों को कुर्सी पर बैठाया, ऐसा भी उन्होंने कहा।

ट्वीट

असम के संसाधन

कांग्रेस की सरकारों ने असम और पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का जो पाप किया था, उसका बड़ा खामियाजा देश की सुरक्षा को उठाना पड़ा। बीते 11 वर्षों में हमारे प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ है कि असम के संसाधन वहां के लोगों के ही काम आएं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नए रोजगार और अवसर

मजबूत नीतियों और दूरदर्शी निर्णयों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। टेक्सटाइल, हस्तशिल्प, गिग इकॉनमी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में हो रही प्रगति से युवाओं, महिलाओं, कारीगरों और एमएसएमई के लिए नए रोजगार और अवसर सृजित हो रहे हैं।

-अन्नपूर्णा देवी, महिला विकास मंत्री

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षक समाज के कर्णधार होते हैं। सरकार शिक्षकों के सम्मान, सशक्तीकरण और सहयोग एवं विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

-भजनलाल शर्मा, सीएम, राजस्थान

सुरक्षा व बचाव के उपाय

असम में राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना में 7 हाथियों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। पशुओं का जीवन-चक्र में अलग महत्व होता है। सरकार को ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जानवरों की सुरक्षा व बचाव के उपाय करने चाहिए।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

खबर संक्षेप

बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं होगा माधवन नाम

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के पर्सनैलिटी राइट्स की

रक्षा करते हुए कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्टर की सहमति के बिना कमर्शियल फायदे के लिए उनके नाम, तस्वीरों, एआई और डीपफेक टेक्नोलॉजी का गैर-कानूनी इस्तेमाल करने से रोका है।

दरगाह पर 'चादर' चढ़ाने से रोक की याचिका

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर पीएम नरेंद्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर

'चादर' चढ़ाने से रोकने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष आया। पीठ ने कहा कि सोमवार को सूचीबद्ध नहीं है।

निजी अस्पताल में आग लगी, सभी सुरक्षित

मुंबई। मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में एक निजी अस्पताल में सोमवार दोपहर आग लग गई, जिसके

चलते मरीजों, डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों सहित लगभग 250 लोगों को

अरावली विवाद पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्पष्टीकरण

पर्यावरण की अनदेखी नहीं, नया खनन पट्टा प्रतिबंधित, चंद लोग फैला रहे 'गलत' सूचना

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर फैली अफवाहों और गलत सूचनाओं का खंडन किया है। मंत्री ने कहा कि अरावली हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पीएम की अगुवाई वाली सरकार हमेशा से हरी-भरी अरावली को बढ़ावा देती रही है। कुछ लोग कोर्ट के फैसले पर जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं, लेकिन मैंने फैसले को गंभीरता से पढ़ा है। स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई छूट नहीं दी गई है। भूपेंद्र यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में अरावली के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर फैसला दिया है। यह पहली बार है जब सरकार के हरित आंदोलन को मान्यता मिली है। कोर्ट ने खनन के सीमित उद्देश्य के लिए एक तकनीकी समिति बनाई है।

> अरावली में 20 वन्यजीव अभयारण्य और 4 टाइगर रिजर्व हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कुल अरावली क्षेत्र लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सिर्फ 0.19 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन की संभावना हो सकती है। 90 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र संरक्षित जोन में आएगा

कोर्ट का फैसला वैज्ञानिक संरक्षण पर आधारित

एनसीआर क्षेत्र में कोई खनन अनुमति नहीं दी

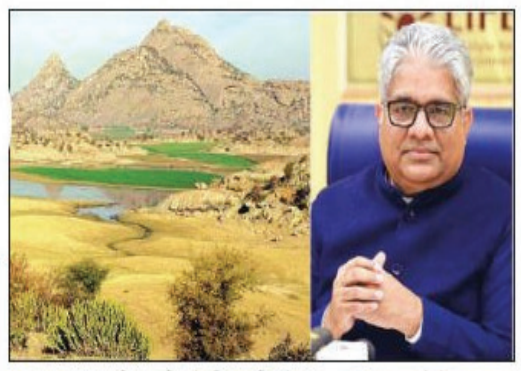

अरावली पहाड़ी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (फाइल फोटो)

100 मीटर से अधिक की आकृति अरावली पहाड़ी

मंत्री यादव ने बताया कि 100 मीटर का मुद्दा 'ऊपर से नीचे' तक है, यानी आसपास की जमीन से 100 मीटर या ज्यादा ऊंची भू-आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। इसके आधार से लेकर पूरी ढलान तक का क्षेत्र संरक्षित होगा। अगर दो पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हैं, तो बीच का क्षेत्र भी अरावली रेंज का हिस्सा होगा। एनसीआर क्षेत्र में कोई खनन अनुमति नहीं है। नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा।

वन्यजीव अभयारण्य सुरक्षित रहेंगे

अरावली में 20 वन्यजीव अभयारण्य और 4 टाइगर रिजर्व हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कुल अरावली क्षेत्र लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सिर्फ 0.19 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन की संभावना हो सकती है। 90 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र संरक्षित जोन में आएगा।

निगरानी और मजबूत होगी

मंत्री ने कहा कि फैसले में सभी गलत आरोपों और अफवाहों को स्पष्ट कर दिया गया है। अवैध खनन ही अरावली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब निगरानी और मजबूत होगी। सरकार ग्रीन अरावली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फैसले से चारों राज्यों में एकसमान नियम लागू हुए हैं, जो पहले दुरुपयोग का कारण बन रहे थे।

राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की मांग

कांग्रेस की राजस्थान इकाई के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। उदयपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के सदस्य कलेक्ट्रेट के बाहर जमा हुए, नारे लगाए और अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। करणी सेना और स्थानीय सामुदायिक समूहों ने अरावली की पहाड़ियों व पर्वतमाला की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को पलटने की मांग की। समूहों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा।

विरोध प्रदर्शन तेज होगा

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार की उच्चतम न्यायालय में अरावली पर्वतमाला को 'पुनर्परिभाषित' करने वाली रिपोर्ट के खिलाफ पूरे राज्य में अपने विरोध प्रदर्शन तेज करेगी। नई परिभाषा से कानूनी सुरक्षा नहीं मिलने के करण 90 प्रतिशत पर्वतमाला नष्ट हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक समिति की अरावली की पहाड़ियों और पर्वतमाला की परिभाषा पर सिफारिशों को 20 नवंबर को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया।

केंद्र सरकार पर बरसीं सीएम ममता

भाजपा के दबाव में आयोग 1.5 करोड़ वोटर्स का नाम हटा रहा

एसआईआर में भारी गलतियां

सीएम ममता बेनर्जी

▶▶ नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बेनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोलकाता में आयोजित पार्टी बैठक में ममता ने कहा कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था की तरह काम नहीं कर रहा, बल्कि भाजपा के निर्देशों पर चल रहा है। भाजपा 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने जैसा है। सीएम ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची तैयार करने में भारी स्तर पर गलतियां हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया जानबूझकर की जा रही है ताकि खास समुदायों के वोट छीने जा सकें। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो पार्षद और पार्टी कार्यकर्ता निष्क्रिय रहेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बूथ स्तर के एजेंटों को सतर्क रहने और मतदाताओं की रक्षा करने का निर्देश दिया।

लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे

सीएम ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मतुआ समुदाय के मताधिकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। ममता बेनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह बिना बंगाल सरकार को जानकारी दिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर रही है और भाजपा के हित साध रही है। केवल टीएमसी के कार्यकर्ता ही राज्य में भाजपा की पैठ रोक सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा बंगाल में मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है।

निलंबित विधायक कबीर ने बनाया नया दल

पश्चिम बंगाल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया। यह कदम उन्होंने

ममता बेनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से निलंबन के कुछ दिन बाद उठाया। उन्हें मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की आधारशिला रखने को लेकर पार्टी से निलंबित किया गया था। बेलडांगा में आयोजित जनसभा में कबीर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में आठ उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि वे खुद मुर्शिदाबाद की रेजीनगर और बेलडांगा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि, पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर अंतिम फैसला बाद में होगा।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मै राजेश कुमार पिता स्व० टेकचंद अग्रवाल अपना पुराना नाम राजेश कुमार को बदल कर अपना नया नाम- राजेश कुमार अग्रवाल पिता स्व० टेकचंद अग्रवाल निवासी पता-मकान नं0 128 वार्ड क्र.-04 भैयाथान रोड पंच मंदिर पारा सूरजपुर, 497229 रख लिया हूँ अतः अब मुझे भविष्य में समस्त शासकीय अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में नया नाम राजेश कुमार अग्रवाल पिता स्व० टेकचंद अग्रवाल से जाना एवं पहचाना जाय।

शपथकर्ता

राजेश कुमार अग्रवाल पता-मकान नं.-128 वार्ड नं.4 भैयाथान रोड, पंचमंदिर पारा सूरजपुर-497229

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क०--2025/2021700052/अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामदास आ० स्व. बुधराम, जाति पनिका, निवासी ग्राम परसा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० द्वारा द्वारा ग्राम परसा स्थित भूमि खसरा न0 1291/3, 1298/2, 1757/21, 2076/1 कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 0.397 हे० भूमि का अनावेदक शिवदास आ० बुधराम, जाति पनिका, निवासी ग्राम परसा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के मध्य खाता विभाजन कराने बाबत आवेदन छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा, 178 के तहत प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 07/01/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।आज दिनांक 16/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार

अम्बिकापुर-2

Name change

I Rajesh Kumar S/O- Late Tekchand Agrawal Resident of-House no.128,ward-04, Bhaiyathan Road, Panch mandir, para, Surajpur, chhattisgarh -497229.hereby declare that have changed my name from Rajesh Kumar S/O -Late Tekchand Agrawal to Rajesh Kumar grawal s/o- Late Tekchand Agrawal in all the Government approved identity Proofs to be used for various purpos-es in the future.

Deponent

Name:-Rajesh Kumar Agrawal S/O- Late Tekchand Agrawal Resident of-House no. 128,ward-04, Bhaiyathan Road, Panch mandir, para, Surajpur,

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क० 202409020700016/ब-121/2023-24

आम सूचना

एतद् द्वारा संध्या सोनी पति उदय कुमार सोनी, निवासी घुटरापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर. जिला सरगजा छ.ग. को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती रामसखी पति स्व. पुरुषोत्तम यादव, निवासी फुन्दुरडिहारी, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित खसरा नबर 194/58 रकबा 0.020 हे भूमि के राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवश अनावेदिका संध्या सोनी पति उदय कुमार सोनी का नाम दर्ज हो गया है, जिसे सुधार करते हुये आवेदिका के नाम पर दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर राजस्व प्रकरण कमांक 202409020700016/ब-121/2023-24 दर्ज कर त्रुटि सुधार हेतु प्रकरण विचाराधीन है। आवेदक पक्ष को आपका सही पता ज्ञात नही होने के कारण नोटिस तामिली नही हो पा रहा समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि उक्त संबंध में आपको कोई अम्पत्ति हो तो पेशी दिनांक 16/01/2026 को न्यायालय में स्थय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 19/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार

अम्बिकापुर

मरीजों का परीक्षण करते हुये नेत्र सर्जन डा. ज्योति सिंह

बस्ती / सत्या मल्टी स्पेशलिटी एंड आई हॉस्पिटल महरीपुर में आयुष्मान धारकों के जनरल मेडिसिन के मरीजों को निशुल्क इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। सत्या मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल महरीपुर फुटहिया कलवारी रोड के प्रबंधक सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि अस्पताल में समय समय पर गरीबों असहायों को निशुल्क दवाइयों एवं जांच की सुविधा उपलब्ध कराता है । अब तक आयुष्मान कार्ड धारकों को आपरेशन होने पर ही आयुष्मान द्वारा इलाज की सुविधा थी किंतु अब हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड धारकों को जनरल भर्ती के मरीजों को निशुल्क इलाज की सुविधा देने की पहल किया है जो कि मरीजों के इलाज के लिए वरदान साबित होगा। सर्जन डा. हनुमान सिंह ने बताया कि सत्या मल्टीस्पेशलिटी एंड आई हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी एवं नेत्र सर्जरी के साथ जनरल मेडिसिन से संबंधित समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज भर्ती एवं ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है । अब जनरल मेडिसिन के मरीजों को आयुष्मान कार्ड धारकों को निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गई है बताया कि साधारण बीमारी जिनमें आपरेशन की जरूरत न हो जनरल मेडिसिंस के इलाज की श्रेणी में आती है जनरल मेडिसिंस की बीमारियों में सांस की समस्या , ब्रोंकाइटिस , अस्थमा , सीओपीडी , टाइफाइड बुखार , फेफड़े की टीबी , डेंगू , शरीर में खून की कमी से , एनीमिया जैसी बीमारियों का निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

देश के इतिहास में पहली बार केरल के जिला अस्पताल में होगा हार्ट ट्रांसप्लांट

एजेंसी ▶▶ तिरुवनंतपुरम

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में पहली बार जिला-स्तरीय अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक 46 साल के व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हुआ था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। अब उसका दिल किसी जरूरतमंद को लगाया जाएगा और ये प्रक्रिया पहल बार किसी जिला स्तरीय अस्पताल में होने जा रही है। वीना जॉर्ज ने बताया कि एक्सीडेंट के कारण ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परिवार ने डोनेशन प्रक्रिया के जरिए अंग दान करने पर सहमति जताई है। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल प्रक्रिया शुरू हो गई है।

मुंबई में डेढ़ घंटे का सफर होगा 10 मिनट में

मुंबई। मुंबई शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 2395 करोड़ की लागत से अब मढ़-वर्सोवा ब्रिज पर समुद्री पुल बनाया जाएगा। मुंबई महानगरपालिका ने इसका ऐलान किया है। यह पुल मढ़ जेट्टी रोड से शुरू होकर वर्सोवा खाड़ी को पार करेगा और वर्सोवा स्थित फिशरीज यूनिवर्सिटी रोड के पास जाकर जुड़ेगा। इससे दोनों इलाकों के बीच की दूरी 20 किमी से से घटकर सिर्फ 2 .6 किमी। इस पुल के बनने के बाद 90 मिनट का सफर महज 10 मिनट में पूरा हो सकेगा। यह पुल 2029 तक पूरा होगा। इस पर करीब 2395 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सर्वे और मिट्टी परीक्षण का काम शुरू हो गया है।

कोहरा में कई गाड़ियां अनियंत्रित होकर भिंडी एक घायल

डाला सोनभद्र। हाथी नाला थाना से महज कुछ दूरी पर रेणुकूट के तरफ सोमवार सुबह लगभग दश बजे डाला के तरफ से जा रहीं ट्रक दुसरे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया जिसके बाद पिछे से आ रही डीसीएम और पिकअप में उसी ट्रक में जा कर टक्कर मारकर दिया जिसमें दो ट्रक एक डीसीएम और पिकअप सहित कुल चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके उपरांत वाराणसी शक्ति नगर राज्य मार्ग पर जाम लग गया जहां हाथी नाला थाना के पुलिस की कड़ी मस्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क किनारे करवाया गया और आवागमन बहाल हुआ वहीं इस सड़क दुघर्टना में केवल एक चालक घायल हो गया जिसको हाथी नाला थाना द्वारा ऐम्बुलेंस से चोपन अस्पताल भेजवाया गया है।

केंद्र सरकार पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साधा निशाना

मनरेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चलाया बुलडोजर

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' में आरोप लगाया कि सरकार ने बिना जनसंवाद, बिना संसद में चर्चा और बिना राज्यों की सहमति के मनरेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। उन्होंने इसे विकास नहीं, बल्कि विनाश करार देते हुए कहा कि इसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीयों को अपनी रोजी-रोटी गंवाकर चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख का हवाला दिया।

न जनसंवाद, न चर्चा, न ही ली कोई सहमति

एक्स पर सोनिया गांधी के लेख का किया जिक्र

सांसद राहुल गांधी, सांसद सोनिया गांधी का प्रकाशित एक लेख

'जी राम जी' बिल गांव विरोधी

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार ने 20 साल के मनरेगा को एक दिन में खत्म कर दिया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को बिना ठीक से जांच पड़ताल किए संसद से पारित करवा दिया। उन्होंने मनरेगा की जगह लाए गए नए विधेयक विकसित भारत जी राम जी को गांव विरोधी करार दिया।

- पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बोलीं

कांग्रेस को 'राम' से ही परेशानी

राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के विरोध पर

कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी दल को 'राम' से ही परेशानी है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुधार कर योजना का नाम 'जी राम जी' कर दिया गया है। सच तो यह है कि कांग्रेस को 'राम' से परेशानी है। हमारे लिए 'राम' ही जिंदगानी है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सीएम भैरों सिंह शेखावत ने अंत्योदय को आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने उनकी इस सोच को गति दी।

'जो कहा, वह किया, और जो नहीं कहा, वह भी करके दिखाया': केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जांजगीर-चांपा जिले के खोखराभाठा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनादेश परब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंच से प्रदेश की उपलब्धियों, जनकल्याण और भविष्य की दिशा पर स्पष्ट संदेश दिया। वंदे मातरम और राज्यगीत के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में जनविश्वास, गौरव और निर्माण के संकल्प को दोहराया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि जो कहा था, वह किया - और जो नहीं कहा था, वह भी करके दिखाया।ह्व उन्होंने दो वर्षों के रिपोर्ट-कार्ड को रेखांकित करते हुए बताया कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के हित में संवेदनशील और परिणामकारी निर्णय लिए हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के पहले महीने में किसानों को 3700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान और बीते दो वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अंतरण अन्नदाताओं के सम्मान का प्रमाण है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए

पारदर्शी भर्ती तंत्र, 32 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता, नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना और आईटीआई के आधुनिकीकरण जैसे कदमों को उन्होंने भविष्य-निर्माण की नींवह्व बताया। महिलाओं के स्वावलंबन हेतु महतारी वंदन योजना और महतारी सदन, पीएम जनमन के तहत 70 लाख परिवारों को लाभ तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट 22 गुना बढ़ा है, 32 अमृत स्टेशन वर्ल्ड-क्लास मानकों पर विकसित हो रहे हैं और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, पीएम-किसान जैसी योजनाओं का व्यापक लाभ आमजन तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार आम जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, चरण पादुका सहित अनेक योजनाओं से विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद की कमर तोड़ने और नक्सल-मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति हुई है। सुरक्षा, पुनर्वास और विकास - तीनों मोर्चों पर समन्वित रणनीति से शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से संसाधन-समृद्ध छत्तीसगढ़ को सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का रोडमैप तय किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अवसरों का राज्य मिल सके। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जांजगीर-चांपा में जनादेश परब का आयोजन जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को एक-एक कर पूरा किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बनने के बाद 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं और विकास के सभी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि सरकार ने लोकतंत्र, जनविश्वास और सुशासन को सुदृढ़ किया है। विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास के नए मानक गढ़ रहा है।

केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर की हत्या पर मुख्यमंत्री श्री साय ने जताया गहरा शोक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। केरल के पलक्कड़ जिले में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर रामनारायण बघेल, निवासी ग्राम करही, तहसील हसौद, जिला सक्ती, के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक और संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी निर्दोष नागरिक के साथ इस प्रकार की हिंसा सभ्य समाज के मूल्यों के विपरीत है और मानवता को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मृतक के परिजनों को तत्काल केरल भेजने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रामनारायण बघेल का पार्थिव शरीर सम्मानपूर्वक उनके गृह ग्राम लाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। पार्थिव शरीर कल हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने केरल सरकार से अनुरोध किया है कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

किसानों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता में मुख्यमंत्री की पहल पर आगामी खरीफ एवं रबी फसलों हेतु प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने तैयारी शुरू

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान हितैषी नितियों एवं फैसलों के जरिए किसानों को समृद्ध करने दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। खेती किसानी को बढ़ावा देने तथा उत्पादन में वृद्धि कर किसानों को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता में है। इसी कड़ी में राज्य सरकार आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026 में किसानों को धान एवं अन्य फसलों के प्रमाणित बीज सहजता के साथ उपलब्ध कराने के दिशा में अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा 31 बीज प्रक्रिया केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न फसलों के लिए कृषकों का 21478 हेक्टेयर रकबा में बीज उत्पादन के लिए पंजीयन कर लिया है। बीज एवं कृषि विकास निगम के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि पंजीकृत बीज उत्पादक कृषकों के प्रक्षेत्र का बीज प्रमाणीकरण संस्था के सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा खड़ी फसलों का निरीक्षण कर लिया गया है। उन्नत एवं प्रमाणित बीजों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया तथा बीज निगम द्वारा कृषकों को बीज लाने हेतु बोरे प्रदाय किये जा रहे है। किसानों से प्राप्त कच्चें बीजों को विभिन्न

बीज प्रक्रिया केन्द्रों में स्थापित बीज ग्रेडर मशीनों के माध्यम से कृषकों की उपस्थिति में संधारण (ग्रेडिंग) का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। खरीफ वर्ष 2026 हेतु संचालक कृषि की मांग के विरूध्द बीज निगम द्वारा लगभग 6,37,520 क्विंटल विभिन्न खरीफ फसलों के प्रमाणित बीज आसानी से उपलब्ध कराये जाने का अनुमान हैं। इस वर्ष किसानों को प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु अग्रिम राशि प्रदान करने के तहत धान मोटा के लिए 1895 रूपए, पतला-सुगंधित धान के लिए 1911 रूपए, सोयाबीन के लिए 4262 रूपए, अग्रिम राशि दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अन्य फसलों में अरहर के लिए 6400 रूपए, उड़द के लिए 6240 रूपए, मूंग के लिए 7014 रूपए शामिल है। निमग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष धान एवं अन्य फसलों के लिए 10 वर्ष के भीतर एवं 10 वर्ष के बाहर की किस्मों पर पंजीयन किया गया है। खरीफ लक्ष्य 26,198.401 हेक्टेयर रकबा के विरूध्द 21,477.633 हेक्टेयर रकबा का पंजीयन किया गया। विभिन्न फसलों के कच्चें बीज का 2,36,503.42 क्विंटल उपार्जित कर लिया गया है। विभिन्न प्रक्रिया केन्द्रों में उपार्जन का कार्य जारी है। इसी प्रकार आगामी रबी 2026-27 हेतु विभिन्न रबी फसलों का बीज वितरण के साथ बीज उत्पादक कृषकों के प्रक्षेत्रों में रबी बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीयन कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस वर्ष रबी सीजन में मांग 1,29,717 क्विंटल के विरूद्ध 1,26,351 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया है, जो कुल लक्ष्य का 97.40 प्रतिशत है। बीज निगम द्वारा लगातार कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के विशेष प्रयासो से अम्बिकापुर क्षेत्र में सुगम आवागमन को नई उड़ान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। अम्बिकापुर क्षेत्र में सुगम आवागमन और ग्रामीण कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19.14 करोड़ रुपये की लागत से 21.78 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इन सड़कों के निर्माण से न केवल ग्रामीण अंचलों का सड़क नेटवर्क सुदृढ़ होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा, कृषि उपज की सुगम आवाजाही और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। स्वीकृत कार्यों में मुडेसा कृष्णापुर मार्ग की 1.08 किमी सड़क निर्माण पर लगभग 93.42 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह खरसूरा रोड-फुलचुही पहुँच मार्ग की 3.63 किमी लंबाई की सड़क के लिए 327.88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे क्षेत्र के कई गाँवों को सीधी सुविधा मिलेगी। गुमगुड़ा खुर्द बतिंकरा मार्ग की 5.51 किमी सड़क के निर्माण पर 423.92 लाख रुपये व्यय होंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी रोड-शंकरपुर खासपारा-मोरमीपारा सड़क की 6.94 किमी लंबाई के लिए 641.15 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे दूर दराज के गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से और अधिक सुदृढ़ हो जाएगा। इसके साथ ही देवीटिकरा रकेली देवगढ़

देवटिकरा खासपारा मार्ग की 2.40 किमी सड़क निर्माण पर 210.36 लाख रुपये तथा रिखी करोंधी खुत्रापारा मार्ग की 2.22 किमी सड़क के लिए 217.38 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं। इन सभी सड़कों के बन जाने से अम्बिकापुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों, विद्यार्थियों, व्यवसायियों और आम नागरिकों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिलेगा। क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में सड़क नेटवर्क सुदृढ़ होगा और किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडी तक पहुंचाने में बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों के लिए स्कूल, अस्पताल तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुँचना आसान होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना भी बढ़ेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत यह 19.14 करोड़ रुपये की राशि अम्बिकापुर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि विकास की धुरी है, इन सड़कों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और व्यापार सभी क्षेत्रों में नई ऊर्जा आएगी। श्री अग्रवाल ने इसके लिए क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी समय में भी अम्बिकापुर क्षेत्र के लिए ऐसे ही विकासोन्मुख कार्यों की श्रृंखला जारी रहेगी, जिससे बढ़ता अम्बिकापुर, सँवरता अम्बिकापुरह्व का लक्ष्य साकार हो सके।

राज्य सरकार ने आगामी वर्ष को महतारी गौरव वर्ष किया घोषित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का पहला वर्ष ह्यविश्वास वर्ष के रूप में समर्पित किया गया था, जिसमें शासन और जनता के बीच विश्वास की पुनर्स्थापना का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए सरकार ने पारदर्शिता, संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से जनता का भरोसा फिर से अर्जित किया। उन्होंने कहा कि सेवा का दूसरा वर्ष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित ह्यअटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के आधारभूत ढांचे,

सामाजिक विकास और जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे हुए। इन उपलब्धियों का विस्तृत ह्यरिपोर्ट कार्डह्ल आज जनता के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया गया, जो सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता का परिचायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश को सबसे अधिक आशीर्वाद मातृशक्ति से मिलता है। माताओं और बहनों के स्नेह, विश्वास और समर्थन से ही सरकार को जनसेवा की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी भाव से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने आगामी वर्ष को ह्यमहतारी गौरव वर्षह्ल के रूप में घोषित किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ह्यमहतारी गौरव वर्ष के दौरान राज्य की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्रबिंदु माताएँ और बहनें होंगी। यह वर्ष न केवल मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक होगा, बल्कि उनके सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक गरिमा को नई ऊँचाई देने का संकल्प भी सिद्ध होगा।

बस्तर संभाग में महिलाएं डेयरी व्यवसाय से बन रही हैं आत्मनिर्भर

कोण्डागांव और कांकेर जिले में पायलट परियोजना संचालित, दुग्ध उत्पादकों को मिल अनुदान और बैंक ऋण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए बस्तर संभाग में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। एनडीडीबी के माध्यम से कांकेर और कोण्डागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित की जा रही। इस योजना में जनजातीय महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 01 जून 2025 को कोण्डागांव जिले के भोंगापाल गांव से इस योजना शुभारंभ किया था। बस्तर संभाग के कोण्डागांव एवं कांकेर जिले के 125 हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान पर दुधारू पशु प्रदाय के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 47 महिलाओं के आवेदन पत्र बैंक से ऋण स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 24 महिलाओं को 36 दुधारू पशु वितरित किया गया है। हितग्राहियों को अच्छे नस्ल की दुधारू गाय प्रदान करने हेतु एनडीडीबी डेयरी सर्विसेस द्वारा साहीवाल नस्ल की गाय (8-10 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन क्षमता) राजस्थान एवं पंजाब क्षेत्र से चिन्हित कर अनुसूचित जनजाति महिलाओं को वितरण किया जा रहा है। दुग्ध महासंघ द्वारा वर्तमान में बस्तर संभाग अंतर्गत 95 कार्यशील दुग्ध समितियों के 4006 दुग्ध प्रदायकों के माध्यम से 15060 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित किया जाकर, लगभग 8000 लीटर दूध प्रतिदिन कांकेर,

कोण्डागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में विपणन किया जा रहा है। बस्तर संभाग में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 वर्षों में 400 नयें ग्रामों को दुग्ध समिति के माध्यम से जोड़ा जायेगा। जिसमें लगभग 9000 दूध प्रदायक जुड़ेगें एवं 48 हजार लीटर दूध संकलन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 28 हजार लीटर क्षमता के दुग्ध शीतलीकरण केन्द्रों एवं एक 1 लाख लीटर क्षमता का नवीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना बस्तर जिले में किया जायेगा। यह योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) की सहायक कंपनी एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेस की मदद से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 2 दुधारू पशुओं की लागत राशि रुपए 1.40 लाख पर 50 प्रतिशत अनुदान 70 हजार प्रदान किया जा रहा है, शेष 40 प्रतिशत बैंक ऋण एवं 10 प्रतिशत राशि हितग्राही को वहन करना होता है। अनुसूचित जनजाति महिला किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है, जो रियायती ब्याज दर पर 4 साल की अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। दुग्ध महासंघ द्वारा ऋण की किश्त हितग्राही किसानों के दूध बिल से कटौती कर बैंक में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना अंतर्गत हितग्राहियों को एक वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क सहायता प्रदान किया जा रहा है, जिसमें- गाय की बीमा (एक साल के लिए), पशु स्वास्थ्य निगरानी उपकरण, 5 किलोग्राम साइलेज चारा, 2 किलोग्राम पशु आहार, एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु प्रतिदिन प्रदान किया जा रहा है। पशु प्रेरण से पहले एवं बाद में वैज्ञानिक पशु प्रबंधन प्रणाली पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशु प्रजनन एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। डेयरी इकाई स्थापना पश्चात अनुसूचित जनजाति महिला हितग्राहियों से घरेलू उपयोग पश्चात अतिशेष दूध का क्रय दुग्ध महासंघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाता है। दुग्ध संकलन को सरल करने के लिए दुग्ध महासंघ द्वारा नये दुग्ध समिति की स्थापना एवं दुग्ध संकलन मार्ग का गठन किया गया है। एक अनुसूचित जनजाति महिला हितग्राही द्वारा लगभग 12 लीटर दूध प्रतिदिन दुग्ध समिति में दिया जा रहा है, जिससे महिला हितग्राही को 1 माह में लगभग राशि रू. 13,000 प्राप्त होता है। जो कि अनुसूचित जनजाति महिला किसानों को उनकी आजीविका बढ़ाने, पोषण में सुधार करने एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

किसानों की सुविधा व पारदर्शिता सम्बंधित अधिकारियों की हो सर्वोच्च प्राथमिकता : जयवर्धन

0 बेहतर शिक्षा परिणाम हासिल करने शिक्षा विभाग को दिये गये आवश्यक निर्देश 0 कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। मंगलवार को यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट आहूत की गई। बैठक में धान खरीदी के प्रगति के संबंध में संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। अद्यतन जानकारी के संबंध मे पूछे जाने पर खाद्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के 54 धान उपार्जन केन्द्रों में सुव्यवस्थित तरीके से धान खरीदी कार्य संपादित किया जा रहा है। उन्होने बताया कि वर्तमान स्थिति तक 20571 किसानों से 115224.04 मे. टन की खरीदी किया गया है। सभी उपार्जन केन्द्रों में नये-पुराने बारदानों का पर्याप्त व्यवस्था है। किसानों द्वारा धान विक्रय उपरांत रकबा समर्पण की कार्यवाही भी की जा रही है। अब तक 5312 किसानों द्वारा स्वेच्छा से 200.7315 हे0 रकबा समर्पण कराया गया है। इसके साथ ही उन्होने बताया कि उपार्जन केंद्र में आने वाले कृषक बंधुओं द्वारा माईक्रो

एटीएम का उपयोग किया जा रहा हैं। कृषकों द्वारा माईक्र एटीएम से लगभग 16.10 लाख रूपये की निष्कासित की गई हैं। वहीं 271.27 करोड़ रूपये किसानो को अब तक किया जा चुका है। बैठक में किसानों की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए शासन द्वारा लिए गये निर्णय जिसके तहत कृषक बंधुओं को 31 जनवरी तक 24×7 तुंहर टोकन एप्प के माध्यम से टोकन प्राप्त होगा, इसका वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार संबंधितों को दिये। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा कृषक बंधुओं से आग्रह किया गया कि वे समय रहते ही तुंहर टोकन एप्प के माध्यम से टोकन प्राप्त करें ताकि उन्हे अपने धान की बिक्री हेतु किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कलेक्टर ने कहा किसानों की सुविधा व पारदर्शिता सभी संबंधित अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता हो। उन्होने कहा किसानों के लिए टोकन के अतिरिक्त समय सीमा और अवधि का विस्तार किसानों का वास्तविक राहत देगा। बैठक में शिक्षा को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें शिक्षा के बेहतर परिणाम हासिल करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। अर्धवार्षिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम व प्री बोर्ड के संबंध में जानकारी ली गई। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित समस्त एसडीएम को अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम जारी होने पर उसके रिव्यू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, एसडीएम व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्व अधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक

राजस्व विभाग की बैठक लेकर कलेक्टर ने अनुविभाग एवं तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने न्यायालयवार राजस्व प्रकरणों एवं उनके निराकरण के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी प्रकरण समय-सीमा के भीतर ही निराकृत किये जाये।

जमीन विवाद पर भाइयों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, 1 की मौत

0 3 घायल, 2 की हालत नाजुक, भेजे गए हायर सेंटर 0 जिला अस्पताल पहुंचे विधायक भूलन सिंह, घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश 0 ग्राम पटना में हुई वारदात

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के ग्राम पंचायत पटना में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दो भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद मंगलवार को हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। जिसमें आनंद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए यहां जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार पश्चात दो आहतों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अम्बिकापुर हायर सेंटर रिफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, जमीन बिक्री को लेकर एक पक्ष द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद विवाद भड़क उठा और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना में श्रीमती बसंती गंभीर रूप से घायल हुईं, जिनका उपचार यहां जिला चिकित्सालय में जारी है। वहीं, चित्रांग और भोले सिंह की हालत नाजुक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए अम्बिकापुर रेफर किया

गया है।घटना की सूचना मिलते ही प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी जिला चिकित्सालय पहुंचे। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, जिला महामंत्री शशिकांत गर्ग, जिला कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राजलाल राजवाड़े, नीरज कुमार गुप्ता, पवन साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक श्री मरावी ने मृतक के परिजनों से भेंट कर संवेदना व्यक्त की और चिकित्सकों को निर्देश दिए कि घायलों को त्वरित व बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ विधायक ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोतवाली पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच में जुटी है।

जीर्णोद्धार के बाद जलाशय किसानों के लिए बना वरदान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के भैयाथान विकासखंड स्थित ग्राम डुमरिया में वर्ष 1989 में निर्मित डुमरिया जलाशय योजना का जीर्णोद्धार क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित होगा।

480 मीटर लंबे इस बांध की जल भराव क्षमता 0.595 मिलियन घन मीटर है, जो 1.76 वर्ग मील कैचमेंट एरिया में फैला हुआ है। जीर्णोद्धार से पहले वर्ष 2000-2001 में जहां मात्र 30 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव थी, वहीं मरम्मत एवं सुधार कार्यों के बाद अब खरीफ मौसम में 160 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस जीर्णोद्धार से डुमरिया, बंसीपुर एवं करोंधा गांव के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जलाशय ने न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है।

उत्कृष्ट आंबा निर्माण हेतु कलेक्टर के हाथों सम्मानित हुए सरपंच

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को कलेक्टर एस. जयवर्धन ने उत्कृष्ट आंगनबाड़ी निर्माण उल्लेखनीय योगदान देने वाले सरपंचों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिले के सभी जनपदों से एक-एक उत्कृष्ट आंगनबाड़ी बनाने वाले सरपंचों को यह सम्मान प्रदान किया गया। सम्मानित सरपंचों में जनपद भैयाथान के ग्राम पंचायत धरतीपारा की सरपंच श्रीमती सविता सिंह, जनपद ओडगी के ग्राम पंचायत इंदरपुर के सरपंच शिव प्रसाद सिंह, जनपद प्रतापपुर के ग्राम

पंचायत डंडकरवा की सरपंच श्रीमती रंगबस मरावी शामिल रहीं।इसके अलावा जनपद प्रेमनगर के ग्राम पंचायत नवापाराकला के सरपंच प्रभु नारायण श्याम, जनपद रामानुजनगर के ग्राम पंचायत मोहनपुर की सरपंच सुमित्रा सिंह एवं जनपद सूरजपुर के ग्राम पंचायत डेडरी के सरपंच कमता प्रसाद सिंह को भी सम्मानित किया गया। परिणाम स्वरूप यह सम्मान आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरपंचों के समर्पण पर दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

साक्षरता कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान पर डॉ. मोहन कलेक्टर के हाथों सम्मानित

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत एक सघन अभियान चला करके और असाक्षरों के चिन्हांकन पंजीयन करते हुए वृहद स्तर पर घर-घर पहुंचकर तथा विविध माध्यमों से असाक्षरों को अध्ययन केन्द्रों में लाने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। जिसके कारण 7 दिसंबर महा परीक्षा अभियान में गांव-गांव में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए निर्धारित परीक्षा केंद्रो में जाकर उल्लास के साथ परीक्षा में शामिल हुए। जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिसमें जिले के कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले के दिशा निर्देश तथा जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में साक्षरता गतिविधियों के नियमित संचालन पठन-पाठन चिन्हांकन सर्वे का कार्य तथा उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके सरगुजिहा बोली भाषा में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाने के लिए परीक्षा में शामिल कराया गया। जिले में उल्लास की श्रेणी में आने वाले 90 प्रतिशत लोगों ने अपनी सहभागिता दी विशेष रुचि महिलाओं में रही तथा उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। साक्षरता गतिविधियों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए कलेक्टर द्वारा जिला परियोजना अधिकारी डॉ. मोहन साहू को समय सीमा की बैठक में प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

प्रशासन द्वारा तीन माह के आश्वासन पश्चात 9वें दिन समाप्त हुआ आंदोलन

बिजली की मांग को लेकर बिहारपुर में अनिश्चिकालीन हड़ताल कर रहे थे ग्रामीण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। बिजली की समस्या को लेकर बिहारपुर क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन आखिरकार जिला प्रशासन के हस्तक्षेप और तीन माह के ठोस आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। आंदोलन का यह मंगलवार को नौवां दिन था। लंबे समय से बिजली से वंचित ग्रामों के ग्रामीण 15 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे हुए थे और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई थी।

आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए भैयाथान अनुविभागीय अधिकारी चांदनी कंवर वन परिक्षेत्राधिकारी तथा विद्युत विभाग के जिला अधिकारियों को आंदोलन स्थल पर भेजा गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों, ग्राम

प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से सीधी और सार्थक चर्चा की। प्रशासनिक अधिकारियों ने आंदोलनकारियों का विश्वास हासिल करते हुए उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और समाधान की दिशा में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। चर्चा के दौरान विद्युत विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा अविद्युतकृत ग्रामों में बिजली विस्तार हेतु उच्च कार्यालय को भेजे गए प्रस्तावों की जानकारी साझा की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि वन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है, जिससे अब बिजली लाइन विस्तार के कार्य में कोई तकनीकी या विभागीय बाधा नहीं रहेगी।

प्रशासन की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया कि जैसे ही विद्युत लाइन विस्तार के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होगी, अविलंब कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। कार्य स्वीकृति एवं प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अधिकतम तीन माह की समय-सीमा तय की गई, जिस पर आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण सहमत हुए।

प्रशासनिक आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि तय समय-सीमा में कार्य प्रारंभ कर वर्षों से चली आ रही बिजली समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा।

मतदाता सूची प्रकाशन के संबंध में हुई राजनीतिक दलों की बैठक

बूथवार मुद्रित व डिजिटल प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां करायी गई उपलब्ध

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन के संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस. जयवर्धन ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जिले में संपादित एसआईआर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची 23 दिसम्बर को प्रकाशित किया गया है । बैठक के दौरान मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित व डिजिटल प्रतियां सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गयी। साथ ही बताया गया कि सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट एवं जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। दावा एवं आपत्ति अवधि 23 दिसम्बर से 22 जनवरी 2026 के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा अपात्र नाम कटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को किया जाएगा।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने

बताया कि जो युवा वोटर 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 साल के हो गए हैं या 1 अक्टूबर 2026 तक हो जाएंगे, उन्हें फार्म-6 में घोषणा पत्र के साथ आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी योग्य युवा वोटरों के नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए पूरे राज्य में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उन्होन आगे बताया कि सभी मतदाताओं एवं सभी राजनैतिक दलों की सहभागिता से 18 दिसंबर तक, 7,40,212 मतदाताओं में से 6,65,504 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवाए, जो एसआईआर के प्रथम चरण में व्यापक सहभागिता को दर्शाता है। इस चरण की सफलता 03 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 16 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 18 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तथा 889 मतदान केंद्रों पर तैनात बीएलओ के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उन्होने बताया कि प्रमुख राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों सहित क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय सहभागिता की तथा तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1690 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए।

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी ने प्रतापपुर के दूरस्थ क्षेत्रों किया निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत भारत सरकार, नीति आयोग द्वारा नामांकित सेंट्रल प्रभारी मनीष मुखर्जी द्वारा जिले के आकांक्षी ब्लॉक प्रतापपुर के दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों का दो दिवसीय विस्तृत सर्वेक्षण एवं निरीक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के दौरान ब्लॉक के विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समग्र आकलन किया गया।

ब्लॉक के विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों की स्थिति का किया गया समग्र आकलन

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विकसित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का संतोषजनक एवं प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। वहीं, अविकसित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच तथा आजीविका के अवसरों का अभाव जैसी समस्याएँ सामने आई उन समस्याओं को समय पर सुधारने की निर्देश दी।

सर्वेक्षण एवं निरीक्षण के उपरांत ब्लॉक के समग्र विकास को गति प्रदान करने हेतु अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं में सुधार, कौशल विकास, रोजगार सृजन तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान की गईं।

इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विभागों के संकेतकों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके त्वरित समाधान हेतु प्रभावी उपायों पर विशेष बल दिया गया। विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस भवन बनवाने, मृदा परीक्षण कार्ड के वितरण, गर्भवती महिलाओं को प्रदान किए जाने वाले रेडी-टू-ईट आहार की पोषण ट्रैकर में शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं में प्रगति लाने हेतु संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। बैठक में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शिक्षा विभाग से विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कृषि विभाग से वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से खंड चिकित्सा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पशु चिकित्सा अधिकारी, जिले से सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा आकांक्षी ब्लॉक फेलो उपस्थित रहे।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन प्रक्रियाओं की तिथि निर्धारित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) की पात्रता रखते हैं, उनके लिए शिक्षा सत्र 2025-26 में छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट इन पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026, ड्राफ्ट प्रस्ताव हेतु 05 फरवरी 2026, स्वीकृति आदेश लॉक करने हेतु 08 फरवरी, जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 तथा छात्रवृत्ति भुगतान जारी करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों के पश्चात् उक्त पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जायेगा एवं ड्राफ्ट प्रपोजल, सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। इसलिये सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय सक्रिय बैंक खाता व आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक डॉ. जे.के. सिंह को मिला सीजी एपीआईकॉन-2025 अवार्ड

स्टेथोस्कोप और बीपी जांच मशीन के साथ एक कमरे में वर्ष 1983 में की प्राइवेट प्रेक्टिस की शुरूआत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक एवं जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉ. जे.के. सिंह को छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के सम्मेलन में 'सीजी एपीआईकॉन 2025 लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि न केवल डॉ. जे.के. सिंह की चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बल्कि मरीजों के प्रति उनकी निष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। साथ ही अस्पताल को उपलब्ध सुविधाओं और चिकित्सा मानकों को परखने के बाद राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, एनएबीएच से मान्यता मिली है, इसे प्रबंधन बड़ा एचीवमेंट मान रहा है।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर जांच मशीन के साथ वर्ष 1983 में प्राइवेट प्रेक्टिस की ओर कदम रखे डॉ. जे.के. सिंह ने एक मरीज और डॉक्टर के बीच के संबंधों और स्वजनों की सोच को साझा किया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा गृहग्राम उत्तर प्रदेश में लेने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई अंबिकापुर में की। डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद उनके परिवार की सोच थी, कि वे शासकीय चिकित्सालयों में अपनी सेवा दें, इसके लिए काफी दबाव भी बना। बाद में उत्तर प्रदेश में रहकर चिकित्सा पेशा की शुरूआत करने की बात हुई, लेकिन सरगुजांचल में शिक्षा के दौरान बने मित्रवत संबंध उन्हें अंबिकापुर तक खींच लाया। शुरूआती दौर में 200 रुपये में किराए का मकान लेकर डिस्पेंसरी की शुरूआत और 300 रुपये में रहने के लिए किराए का मकान लिया। महज 10 रुपये परामर्श शुल्क और एक रुपये की दवा की पुड़िया का वे मरीजों से लेते थे। पहले माह में उन्हें मरीजों का इलाज करने के एवज में मात्र 575 रुपये प्राप्त हुए, जिससे मकान और डिस्पेंसरी का किराया निकल गया। धीरे-धीरे मरीज बढ़ते गए और ब्लड सेंपल लेकर जांच के लिए लेकर खुद अन्य चिकित्सक के यहां जाने लगे, उन्हें स्वयं ब्लड सेंपल की जांच करने की अनुमति मिल गई थी। गंभीर स्थिति में मरीज होने की स्थिति में अंबिकापुर के होली क्रॉस अस्पताल या जिला अस्पताल की मदद लेनी पड़ती थी।

बीमार की पूरी हिस्ट्री लेने के बाद करते हैं इलाज

वर्ष 1995 में कंप्यूटर प्रचलन में आने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र का विकास हुआ, जांच की सुविधाएं भी बढ़ीं। इसके साथ ही उनकी सोच अस्पताल खोलने की दिशा में विकसित हुई। मरीज को उनकी वजह से नुकसान न हो, इस ध्येय को लेकर उन्होंने अपने अस्पताल को सुपर स्पेशिलिटी सुविधाओं से परिपूर्ण किया। चिकित्सा सेवा में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करने का परिणाम है कि आज उनके यहां 250 से अधिक स्टाफ यहां आने वाले मरीजों का ख्याल रखते हैं। डॉ. जे.के. यिंह ने कहा कि आज भी वे किसी गंभीर मरीज की हिस्ट्री पूरी तन्मयता से लेते हैं, ताकि संबंधित मरीज को सही जांच और इलाज की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि शासकीय अस्पतालों या यहां से निकलकर प्राइवेट अस्पताल खोलने वाले कई चिकित्सकों का 95 प्रतिशत जांच में भरोसा है, जबकि मरीज की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए 50 प्रतिशत बीमारी की हिस्ट्री का ज्ञान होना जरूरी है।

सिक्स एडिशन का बना अस्पताल

जीवन ज्योति अस्पताल के संचालक डॉ. जे.के सिंह ने बताया कि उनके यहां केरल, बेल्लोर जैसे शहरों से ऑडिट के लिए टीम आई थी, जिन्होंने सभी को अपने काम में लगे रहने कहा और एक कर्मचारी के साथ अस्पताल में मरीजों को मिल रही एक-एक सेवाओं का जायजा लिए। एक-एक कर्मचारियों से बातचीत करके कई प्रकार की जानकारी ली, और बिना कुछ बताए चले गए। इसी ऑडिट के बदौलत उनके अस्पताल को एनएबीएच, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता मिली है। स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता का एक प्रमुख मानक, अस्पतालों के लिए एनएबीएच प्रत्यायन मानकों का सिक्स एडिशन है, जो अस्पतालों को उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। इसका आंकलन करने और ऑडिट टीम की रिपोर्ट के बाद सिक्स एडिशन के अस्पताल के रूप में जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पहचान बनी है। उन्होंने कहा एनएबीएच के प्रोटोकॉल को फॉलो करके और मानकों पर खरा उतरने के बाद ही इस उपलब्धि को हासिल किया जा सकता है। इस मौके पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल की डायरेक्टर संध्या सिंह, वरिष्ठ पार्षद विजय सोनी के अलावा जीवन ज्योति अस्पताल के अन्य चिकित्सक व स्टाफ उपस्थित थे।

मेट्रो सिटी के तर्ज पर उपलब्ध आईवीएफ सुविधाएं

श्री आईवीएफ क्लिनिक की विशेषज्ञ व अनुभवी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट लेप्रोस्कोपी सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. स्नेहा सिंह ने इस मौके पर बताया कि आईवीएफ क्लिनिक की स्थापना से क्षेत्र के उन दंपतियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। आने वाले समय में यह केंद्र आधुनिक तकनीक और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का नया अध्याय जोड़ेगा। यहां मेट्रो सिटी के तर्ज पर आईवीएफ से संबंधित सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। 12 दिसम्बर को श्री आईवीएफ क्लीनिक प्रारंभ होने के बाद एक सप्ताह के अंतराल में संतान की चाहत रखने वाले कई दंपति उनके संपर्क में आ चुके हैं। इनकी काउंसलिंग करके उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिस पर उन्होंने संतोष जताया है। डॉ. स्नेहा ने बताया यह सिर्फ गर्भधारण की एक आधुनिक मेडिकल तकनीक है इससे बच्चों की सेहत पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने महिला प्रजनन प्रणाली, गर्भाशय के हिस्से में कैंसर जैसे अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉ. आकाश सिंह ने बताया कि आईवीएफ के लिए जो भी जांच सुविधा होनी चाहिए वह सभी सुविधा मेट्रो सिटीज की तरह हमारे पास उपलब्ध है। अत्याधुनिक उपकरण उच्चतम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, जिससे प्रभावित और सटीक उपचार के लिए सर्वोत्तम परीक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं।

क्रिसमस पर्व मनाने कड़ाके की ठण्ड में आज उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। क्रिसमस पर्व के मौके पर नगर के नवापारा स्थित बेदाग ईशमाता महागिरजाघर में रात्रि कालीन पूजन विधि का अनुष्ठान आज 24 दिसम्बर को 10 बजे से प्रारंभ होगा जो महामहिम बिशप डॉ. अन्तोनिस बड़ा धर्माध्यक्ष अंबिकापुर धर्मप्रान्त के मौजूदगी में संपन्न होगा। प्रात: कालीन अनुष्ठान 7 बजे प्रारंभ होगा।

नमनाकला स्थित संत इग्नासियुस चर्च में रात्रि कालीन आराधना 9 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें विशप पतरस मिंज ये.स., सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष अंबिकापुर धर्मप्रान्त, पूजन विधि का अनुष्ठान करेंगे। इसके साथ क्रिसमस का पर्व अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया जाएगा। प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में 24 दिसंबर की मध्यरात्रि से भव्य आयोजन होगा। इस अवसर पर धर्मप्रान्त के कई पुरोहित, धर्मबहनें तथा मसीही समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। क्रिसमस पर्व को लेकर महागिरजाघर में भव्य तैयारियां की गई हैं। महागिरजाघर परिसर को क्रिसमस के पारम्परिक प्रतीकों, रोशनी, सितारों तथा क्रिसमस ट्री से सजाया गया है। पूरे वातावरण में आध्यात्मिक उल्लास और पवित्रता की अनुभूति होने लगी है।

सर्व समाज आज करेगा नगर बंद, धरना व चक्का जाम

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के दौरान ईसाई मिशनरी द्वारा घटित कथित घटना के विरोध में सर्व समाज द्वारा 24 दिसंबर बुधवार को शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन, सभा, चक्का जाम एवं नगर बंद का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में प्रशासन को पूर्व सूचना देते हुए बताया गया है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक नगर बंद रखा जाएगा। साथ ही दोपहर एक बजे से 3:30 बजे तक स्थानीय गांधी चौक में धरना-प्रदर्शन एवं सभा आयोजित की जाएगी। उक्ताशय की जानकारी रूपेश दुबे ने दी ।

पुराने बस डिपो में उच्च स्तरीय जलकुंड के कार्य का शुभारंभ

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पुराने बस डिपो में स्वीकृत 10 लाख लीटर क्षमता वाले नए उच्च स्तरीय जलकुंड के कार्य का शुभारंभ 23 दिसम्बर को नगर पालिक निगम की महापौर मंजूषा भगत, सभापति हरमिंदर सिंह(टिन्नी, महापौर परिषद के सदस्य जितेंद्र सोनी, वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे ने किया। इस मौके पर पार्षद राहुल त्रिपाठी, रविंद्र गुप्ता भारती, प्रियंका गुप्ता, आकाश गुप्ता, मनोज गुप्ता, विकास गुप्ता सहित अन्य वार्ड निवासियों की उपस्थिति रही। बता दें कि पुराने बस डिपो में स्वीकृत 10 लाख लीटर क्षमता वाले नए उच्च स्तरीय जलकुंड के कार्य के लिए अधोसंरचना मद अंतर्गत 107.76 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त जलकुंड को भरने के लिए राइजिंग मेन पाइप लाइन के विस्तार हेतु मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत 73.84 लाख रुपये की स्वीकृत की गई है। इसके लिए कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। उपरोक्त जल टैंक के पूरा होने के बाद, शीतला वार्ड क्रमांक 32, रामानुज वार्ड क्रमांक 33, ब्रह्म वार्ड क्रमांक 34, स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 35 और अग्रसेन वार्ड क्रमांक 38 के निवासियों को आवश्यकता अनुसार पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर अंबिकापुर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंता तथा निकाय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

संविदा पदों की भर्ती हेतु 30 तक तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सरगुजा जिला हेतु रिक्त संविदा पदों विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक के 02 पद, क्षेत्रीय समन्वयक 10 पद एवं लेखा सहायक 06 पद, कुल 18 पदों हेतु प्रकाशित चयन सूची व प्रतीक्षा सूची के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त दावा-आपत्ति का समिति द्वारा परीक्षण किया गया। चयन समिति द्वारा प्रकाशित चयन सूची/प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों में प्रकाशित सूचना अनुसार एवं विहित मापदण्डों के अनुसार अनुभव वर्ष की गणना एवं मूल्यांकन में विसंगतियां पाई गई, इसके अनुसार प्रकाशित चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची 31 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया। उन्होंने बताया कि चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय उपरांत पदवार, पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं अपात्र सूची का प्रकाशन करते हुए, दावा/आपत्ति आमंत्रित की जा रही है। सूची पर अभ्यर्थी अपना दावा/आपत्ति 30 दिसंबर को सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा, अंबिकापुर में जमा कर सकते है। अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत दावा/आपत्ति, केवल मूल आवेदन पत्र के आधार पर ही मान्य किए जाएंगे। कोई भी नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी प्रकार के दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जाएंगे। दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात वरियता सूची से चयन की प्रक्रिया की जाएगी।

वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होगी धान उठाव की मॉनिटरिंग, अवैध धान पर करें कार्रवाई

कलेक्टर अजीत वसंत ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में दिए कई निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने मंगलवार को साप्ताहिक समय सीमा की पहली बैठक ली। उन्होंने कहा कि शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ आमजनों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। गम्भीरतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर जिले में जारी धान खरीदी की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए जिले में अब तक की गई खरीदी, खरीदी केंद्रों में किसानों हेतु व्यवस्था एवं सुविधाओं, संवेदनशील केंद्रों, अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन पर की जा रही कार्रवाई सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी ली।

कलेक्टर ने कहा कि पात्र किसानों को धान खरीदी में किसी प्रकार की समस्या ना हो, अवैध धान पर कार्रवाई हो। राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम नियमित खरीदी केंद्रों में जाकर

जांच करें। उन्होंने किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या समस्या की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित किया तथा कहा कि सभी समितियों में उपार्जन प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध होनी चाहिए। धान का समय पर उठाव, रकबा समर्पण, सत्यापन कार्रवाई सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि राइस मिलरों द्वारा उठाव की जांच हेतु जिला स्तर पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। गाड़ी में धान लोड करने के पश्चात समिति के कर्मचारी जिला कार्यालय में बनाए गए सेंटर के मोबाइल नंबर पर विडियो कॉलिंग कर उक्त धान लोड गाड़ी का विवरण सहित सत्यापन कराएंगे, कि वास्तव में कितना धान लोड है, जिससे कि समिति से धान की वास्तविक उठाव की जांच की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

बैठक में कलेक्टर ने विभागों में जारी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी विभाग जिनमें विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है। वे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, नियमानुसार, निर्विवादित होना सुनिश्चित करें। प्रक्रिया में लापरवाही की शिकायत प्राप्त ना हो, इसका ध्यान रखें। बैठक में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अपार आईडी में बच्चों की शत-प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करें। ऐसे बच्चों की सूची उपलब्ध कराएं, जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। सभी एसडीएम प्रकरण तैयार कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कार्रवाई करें, ताकि अपार आईडी में एंट्री में समस्या ना हो। वहीं ऐसे बच्चे जो आगामी शिक्षा सत्र में पहली कक्षा में भर्ती लेंगे, उनका जाति प्रमाणपत्र बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ऑपरेटर की ट्रेनिंग आयोजित करें, ताकि आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और समय सीमा में निराकरण किया जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्राथमिकता के साथ आवास पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। आवास चौपाल लगाकर हितग्राहियों से बात कर निर्माण के दौरान आ रही समस्याओं का निराकरण करें तथा उन्हें तेजी से कार्य पूर्ण कराने प्रोत्साहित करें। उन्होंने बैठक में कहा कि शासकीय भूमि में अतिक्रमण पर कार्रवाई हो। जिले में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों पर नियमानुसार निराकरण करने निर्देशित किया। बैठक में समय सीमा के विभागवार लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर जनदर्शन अब हर मंगलवार को

बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि आम जनता की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टर जनदर्शन अब प्रत्येक मंगलवार को प्रात: 11 बजे से आयोजित होगा। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक, राम सिंह ठाकुर, अमृत लाल ध्रुव, नगर निगम कमिश्नर डीएन कश्यप सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने रैन बसेरा व आश्रय स्थल का किया निरीक्षण

शीतलहर को देखते हुए बिस्तर व कंबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। जिले में बढ़ते शीतलहर को देखते हुए जरूरतमंद एवं निराश्रित लोगों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्टर अजीत वसंत ने प्रतीक्षा बस स्टैंड परिसर में नगर पालिक निगम अंबिकापुर द्वारा संचालित रैन बसेरा एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित आश्रय स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रैन बसेरा एवं आश्रय स्थल में साफ-सफाई की व्यवस्था, ठहरने वाले लोगों के लिए बिस्तर एवं कंबल की उपलब्धता तथा सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए, ताकि ठंड के मौसम में आश्रय लेने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कलेक्टर ने शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग रैन बसेरा एवं आश्रय स्थल का लाभ उठा सकें। निरीक्षण के दौरान नगर पालिक निगम आयुक्त डी.एन. कश्यप सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

शिविरार्थी छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति, यातायात नियमों की मिली जानकारी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। नवा बिहान नशामुक्ति जागरूकता अभियान सरगुजा ने पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, रिसर्च एण्ड मैनेजमेंट बीएड कॉलेज के रासेयो छात्र-छात्राओं को नशा मुक्ति, यातायात के संबंध में जागरूक किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा अमोलक सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में सरगुजा पुलिस एवं नवा बिहान नशामुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र सरगुजा के द्वारा निरंतर जन समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत भवन चठिरमा में बौद्धिक परिचर्चा में

पहुंचे मुख्य अतिथि उप निरीक्षक अभय तिवारी ने छात्र-छात्राओं को यातायात के प्रावधानों के संबंध में आंकड़ों सहित रोचक ढंग से जानकारी दिया। विशिष्ट अतिथि संयोजक नवा बिहान मंगल पाण्डेय ने नशा, नशे की लत, नशे के विभिन्न उत्पादों एवं नशे की लत लगने के कारणों सहित नशे की लत के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। साथ ही व्यक्तित्व विकास विषय पर छात्र-छात्राओं की समझ विकसित की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में अरूण कुमार दुबे कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, जयमाला सिंह सहायक कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, चठिरमा ग्राम पंचायत सरपंच सोनिया पण्डो एवं जनपद पंचायत सभापति विजय व्यापारी का सराहनीय योगदान रहा।

अज्ञात वृद्ध की इलाज के दौरान मौत

अंबिकापुर। सीतापुर स्वास्थ्य केंद्र से रेफर किए गए अज्ञात वृद्ध की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लम्बे समय तक चले इलाज के बीच मौत हो गई। मृतक को 2 नवम्बर को सीतापुर के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के बाद 3 नवम्बर को जिला अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया था। 21 दिसम्बर को वृद्ध की मौत के बाद पुलिस ने शव को मर्च्युरी में रखवाया है। अस्पताल के पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी ने जिले के सभी थानों में वृद्ध का फोटो उपलब्ध कराते हुए स्वजनों का पता चलने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर भेजने का आग्रह किया है, ताकि शव को उनके सुपुर्द किया जा सके।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर